

कीमतें और मुद्रास्फीति: नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी

वर्ष 2022 में भारत में तीन चरण में उपभोक्ता मुद्रास्फीति हुई। इसके चरम तक पहुँचने का चरण अप्रैल 2022 तक था जब यह 7.8 प्रतिशत तक पहुँच गई थी, इसके बाद स्थिरता का चरण अगस्त 2022 तक था जब यह 7.0 प्रतिशत बनी रही फिर दिसंबर, 2022 तक इसमें कमी आई और यह लगभग 5.7 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसमें वृद्धि का कारण रूस-यूक्रेन युद्ध के नतीजों और देश के कुछ भागों में अत्यधिक गर्मी के कारण फसल की कटाई में कमी थी। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए त्वरित और पर्याप्त उपायों ने मुद्रास्फीति में वृद्धि पर लगाम लगाई है और इसे सेंट्रल बैंक की सहनशीलता सीमा के भीतर लाया है। इसके विपरीत, प्रमुख पश्चिमी देश जिन्हें महामारी के दौरान प्रोत्साहन प्रदान किया गया, वे मुद्रास्फीति के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं।

मई, 2022 में अपेक्षाकृत उच्च थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) मुद्रास्फीति और निम्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के बीच अंतर मुख्य रूप से दो सूचकांकों के सापेक्ष भार में अंतर और खुदरा कीमतों पर आयातित इनपुट लागत के विलंबन प्रभाव के कारण बढ़ा। हालांकि तब से मुद्रास्फीति के दो परिमाणों के बीच का अंतर कम हो गया है, जो अभिसरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण उपाय - मुख्य मुद्रास्फीति - स्थिर बनी हुई है। भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के बीच खुदरा मुद्रास्फीति दरों में बड़ा अंतर रहा है।

नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा प्रकाशित हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (एचपीआई) के अनुसार, समाप्त तिमाही (क्यूई) सितंबर, 2021 की तुलना में सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही (क्यूई) में समग्र एचपीआई मूल्यांकन और एचपीआई बाजार मूल्य में समग्र वृद्धि आवास वित्त क्षेत्र में बहाली का संकेत देती है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मई और दिसंबर, 2022 के बीच नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 225 आधार अंक बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी, गेहूँ उत्पादों के निर्यात पर रोक, चावल पर निर्यात शुल्क लगाने, दालों पर आयात शुल्क में कमी और उपकर, खाद्य तेलों और तिलहन पर टैरिफ का युक्तिकरण और स्टॉक सीमा नियत करना, प्याज और दालों के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना और विनिर्माण उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर आयात शुल्क का युक्तिकरण जैसे राजकोषीय उपाय किए हैं।

आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट अवधि में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। सामान्य तौर पर, दुनिया भर में जलवायु तेजी से अनिश्चित हो गई है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि का जोखिम और बढ़ गया है। बहुत कुछ औद्योगिक इनपुट कीमतों पर निर्भर करता है: इनमें कमी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता कीमतों में उनका लाभ पहुँचने में विलंब के कारण प्रमुख मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है।

सामान्य तौर पर, वर्ष 2022 को, तीन से चार दशकों के बाद आधुनिक विश्व में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी के रूप में चिह्नित किया गया था। भारत में, सरकार और केंद्रीय बैंक ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाए। अप्रैल, 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य सीमा से पार बढ़ना विश्व की तुलना में सबसे कम था। हमें विश्वास है कि यदि वर्ष 2023 में भारत में मुद्रास्फीति का दबाव फिर से उभरता है तो प्राधिकरण सतर्क रहेंगे और वर्ष 2022 की तरह ही सक्रिय रहेंगे।

परिचय

5.1 बढ़ती कीमतें हमेशा नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण होती हैं क्योंकि वे आम आदमी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के संकट अधिक महसूस किए जाते हैं, जहां विकसित देशों की तुलना में उपभोग विविधता में आवश्यकताओं का हिस्सा अधिक होता है। हाल के वर्षों में, भारत की मुद्रास्फीति की दर अच्छी रही है, जो 2017 से 2019 तक आरबीआई के लक्ष्य दर 4 प्रतिशत से काफी नीचे है।

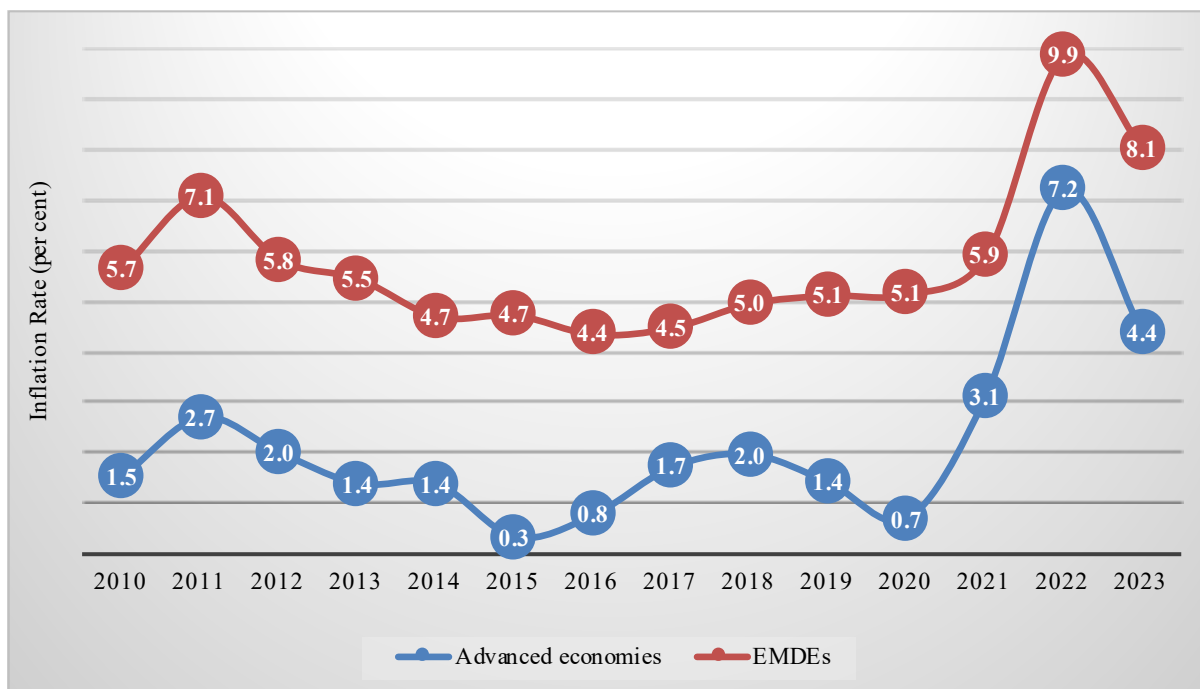
5.2 वर्ष 2020 में, आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं ने मुद्रास्फीति को आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी छूट सीमा से परे पहुंचा दिया। महामारी ने आवश्यक वस्तुओं, भोजन, दवा और औद्योगिक सामानों के मामले में आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं के माध्यम से मांग की तुलना में आपूर्ति को अधिक प्रभावित किया। परिणामतः, इसने देश में लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया।

5.3 जैसे-जैसे महामारी कम हुई, रूस-यूक्रेन में संघर्ष छिड़ गया, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी, जो ज्यादातर कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थी। कीमतें एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गईं और घरेलू बजट को नुकसान पहुंचाया, जिसने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया। एक स्वस्थ विश्व अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व दरों का सामना करना पड़ा था। मुद्रास्फीति जनित मंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर था। इसकी प्रतिक्रिया में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि करने से, अमेरिकी डॉलर में उछाल आया, जिसके कारण डॉलर-आधारित ईंधन आयात और भी महंगा हो गया।

5.4 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा मुद्रास्फीति की दर को वर्ष 2021 में 3.1 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 1982 के बाद सबसे अधिक है। सितंबर, 2022 में यूरो क्षेत्र में यह दर 10.0 प्रतिशत तक पहुंच गई (डब्ल्यूईओ, अक्टूबर 2022¹)। दिसंबर, 2022 में 6.5 प्रतिशत तक कम होने से पहले जून 2022 में अमेरिकी मुद्रास्फीति अपने 40 वर्षों के उच्च स्तर 9.1 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि यूके में दिसंबर, 2022 में 9.2 प्रतिशत की वार्षिक मूल्य वृद्धि देखी गई। जर्मनी में दिसंबर, 2022 में 8.6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई। उभरते बाजारों में, ब्राजील ने कीमतों के रुझान में कमी देखी, जबकि तुर्की की मुद्रास्फीति दिसंबर, 2022 में थोड़ी सी घटकर 64.3 प्रतिशत होने से पहले अगस्त से नवंबर, 2022 तक 80 प्रतिशत से ऊपर थी। युद्ध ने महामारी के बाद वस्तुओं और सेवाओं की मांग में मजबूत सुधार के प्रभावों को बढ़ा दिया था। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2021 में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 9.9 प्रतिशत हो गई है (डब्ल्यूईओ, अक्टूबर 2022)।

1 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ, अक्टूबर 2022

चित्र V.1: कैलेंडर वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

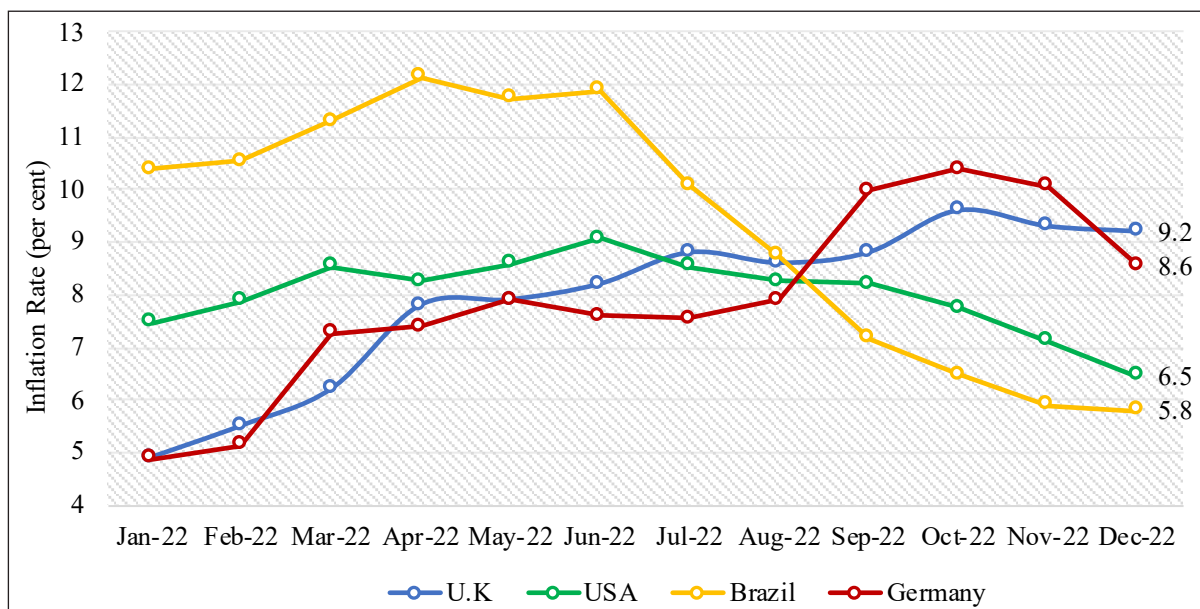


स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2022, आईएमएफ

नोट: *आंकड़े वार्षिक औसत हैं; वर्ष 2022 और 2023 के आंकड़े पूर्वानुमानित हैं।

आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 40 अर्थव्यवस्थाएं और ईएमडीई में 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

चित्र V.2: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति



स्रोत: ओईसीडी

5.5 भारत में सराहनीय मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए नींव पहले ही रख दी गई थी क्योंकि महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए अपनाए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपाय विवेकपूर्ण और अच्छी तरह से कैलिब्रेट किए गए थे। भारत ने अतिउत्साहित न होने का फैसला किया और इसीलिए रूस-यूक्रेन संघर्ष के

कारण मूल्य दबावों को नियंत्रित किया जा सकता था। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और उसके बाद देश के कुछ हिस्सों में हुई असमान वर्षा ने कृषि क्षेत्र पर प्रभाव डाला, जिससे आपूर्ति कम हो गई और कुछ प्रमुख उत्पादों की कीमतें बढ़ गईं। अच्छे मानसून के साथ-साथ पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले त्वरित सरकारी उपायों के कारण दिसंबर, 2022 में 5.7 प्रतिशत तक कम होने से पहले भारत की मुद्रास्फीति की दर अप्रैल, 2022 में 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। वैश्विक आर्थिक मंदी और ब्याज दर में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जिससे थोक मूल्य मुद्रास्फीति में भारी गिरावट हुई है। इस प्रकार, भारतीय निर्माताओं पर इनपुट मूल्य दबाव कम हो गया है।

5.6 यहाँ तक कि थोक स्तर पर मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद, खुदरा कीमतों पर पहले की उच्च इनपुट लागतों का प्रभाव पड़ा है। कोर मुद्रास्फीति लगभग 6 प्रतिशत पर बनी हुई है और इस वर्ष की शुरुआत में आए आपूर्ति संकटों के दूसरे दौर के प्रभावों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, मांग में सुधार के साथ, सेवा मुद्रास्फीति में तेजी आई है। इस पृष्ठभूमि की तुलना में, हम वित्तीय वर्ष 22 और वित्तीय वर्ष 23 में खुदरा और थोक मूल्य मुद्रास्फीति के रुझानों और प्रेरकों, उपभोक्ता मुद्रास्फीति में राज्य-वार और ग्रामीण-शहरी अंतर, ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति, सीपीआई और डबल्यूपीआई अभिसरण, आवासन की कीमतें, दवा मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे तथा अध्याय में आगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय और मौद्रिक नीति के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे।

घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति

प्रमुख मुद्रास्फीति अपनी चरम सीमा से घट गई

5.7 वित्त वर्ष 22 में वित्त वर्ष 21 की तुलना में सीपीआई-संयुक्त (सीपीआई-सी) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कम देखी गई। फिर भी, महामारी से पहले के वर्षों के दौरान देखी गई कमी की तुलना में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही। वित्त वर्ष 22 के दौरान, कुछ उप-समूहों जैसे 'तेल और वसा', 'ईंधन और बिजली' और 'परिवहन और संचार' में उच्च मुद्रास्फीति देखी गई थी। इसका मुख्य कारण महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान था। इसके बाद के वर्ष (वित्त वर्ष 23) की शुरुआत में रूस-यूक्रेन संकट आया, जिसके कारण अप्रैल, 2022 में प्रमुख मुद्रास्फीति की दर उच्च रही।

5.8 वित्त वर्ष 23 में, खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति द्वारा संचालित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति मध्यम स्तर पर रही। अप्रैल और दिसंबर, 2022 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति 4.2 से 8.6 प्रतिशत के बीच रही, जबकि कोर मुद्रास्फीति दर अप्रैल, 2022 को छोड़कर लगभग 6 प्रतिशत पर रही।

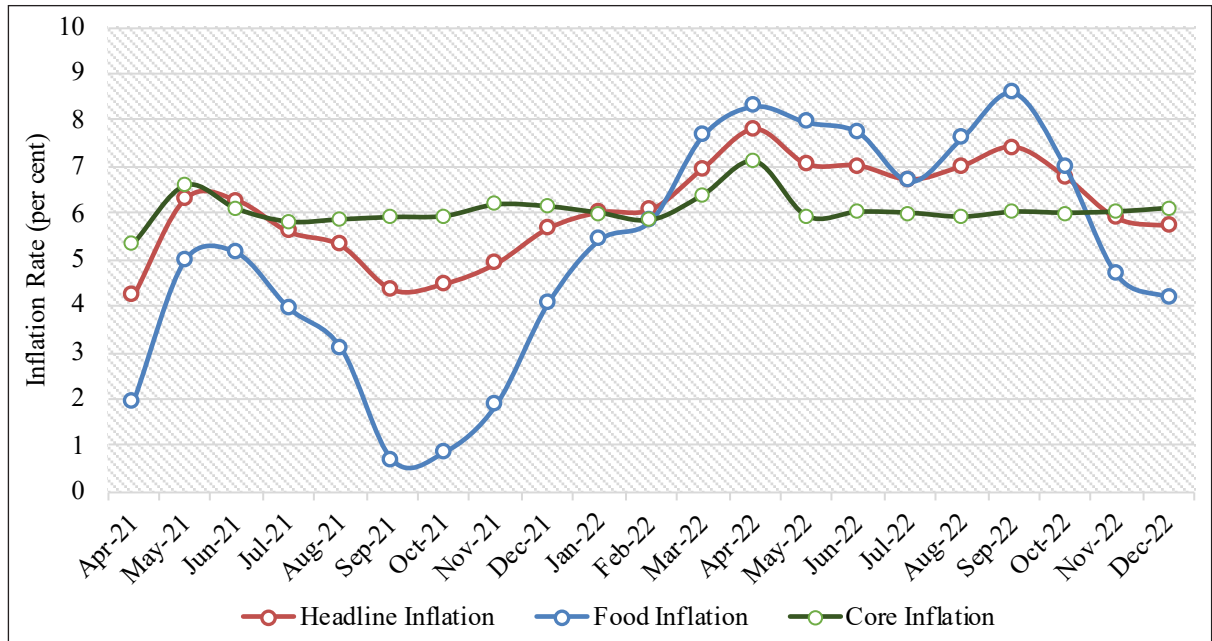
सारणी V.1: सीपीआई-सी के आधार पर औसतन वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति (प्रतिशत) (आधार: 2012=100)

समूह/उप-समूह	भार	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23*
खाद्य और पेय पदार्थ	45.9	6.0	7.3	4.2	7.0
अनाज और उत्पाद	9.7	2.8	3.8	0.5	9.3
मांस और मछली	3.6	9.3	15.4	7.9	4.7
अंडा	0.4	4.5	12.9	7.6	-1.0
दूध और उत्पाद	6.6	2.9	5.4	2.8	6.8
तेल और वसा	3.6	2.9	16.0	27.4	5.4
फल	2.9	0.7	2.6	6.2	4.4
सब्जियाँ	6.0	21.3	5.8	-7.2	7.6
दलहन और उत्पाद	2.4	9.9	16.4	6.0	1.8

	भार	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23*
चीनी और कन्फेक्शनरी	1.4	0.8	2.5	2.3	2.7
मसालें	2.5	4.4	10.9	5.3	14.9
पान, तम्बाकू और नशीला पदार्थ	2.4	4.2	9.9	4.5	2.0
कपड़े और जूते	6.5	1.6	3.4	7.2	9.7
आवासन	10.1	4.5	3.3	3.7	4.1
ईंधन और बिजली	6.8	1.3	2.7	11.3	10.5
विविध	28.3	4.4	6.6	6.7	6.3
घरेलू सामान और सेवाएं	3.8	3.1	3.0	5.8	7.5
स्वास्थ्य	5.9	6.2	5.1	7.5	5.8
परिवहन और संचार	8.6	2.4	9.9	10.1	6.4
मनोरंजन और आमोद	1.7	4.9	5.1	6.5	6.4
शिक्षा	4.5	5.5	2.8	2.9	5.2
प्रमुख मुद्रास्फीति	100.0	4.8	6.2	5.5	6.8
मूल स्फीति	47.3	4.0	5.5	6.0	6.1
खाद्य मुद्रास्फीति	39.1	6.7	7.7	3.8	7.0

स्रोत: एमओएसपीआई,
टिप्पणी *अप्रैल-दिसंबर, दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई आंकड़े अनंतिम हैं

चित्र V.3: खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट



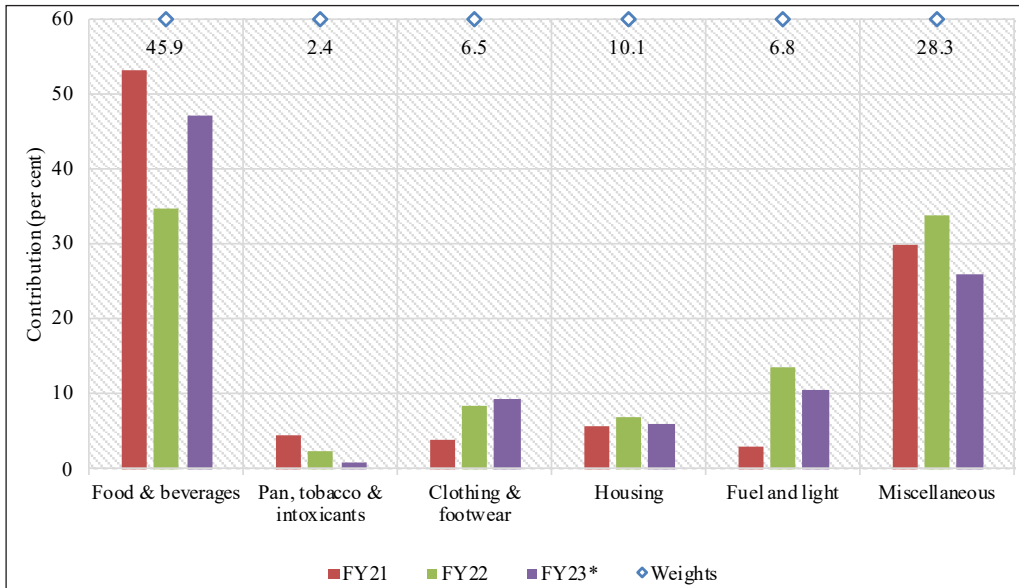
स्रोत: एमओएसपीआई

खाद्य-सामग्री द्वारा प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति

5.9 मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आवास, कपड़ा और भेषज क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, इसके अतिरिक्त आयातित मुद्रास्फीति चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक स्पिलओवर ऊर्जा, खनन, रसायन, व्यापार, बुनियादी और मशीनरी², खुदरा क्षेत्र में मुख्य रूप से थोक मूल्य मुद्रास्फीति के माध्यम से पहुँचता है, में कीमतों के दबाव से प्रेरित होते हैं। वित्त वर्ष 23 के दौरान, 'खाद्य और पेय पदार्थ', 'कपड़े और जूते', और 'ईंधन और बिजली' प्रमुख मुद्रास्फीति में मुख्य योगदानकर्ता थे- प्रथम दो प्रेरकों ने इस वित्तीय वर्ष में पिछले एक प्रेरक की तुलना में अधिक योगदान दिया।

5.10 'विविध' समूह के अंतर्गत, उप-समूहों 'घरेलू सामान और सेवाओं' और 'व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव' में उच्च मुद्रास्फीति देखी गई, जो कि कोविड-19 के बाद की अवधि में उपभोक्ता मांग के पुनरुद्धार के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 22 की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में 'स्वास्थ्य' उप-समूह में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है। तथापि, शिक्षा उपसमूह में मुद्रास्फीति महामारी के बाद व्यक्तिगत वर्गों के लिए फिर से खुलने वाले स्कूलों के कारण बढ़ी।

चित्र V.4: 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह द्वारा प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति



स्रोत: एमओएसपीआई

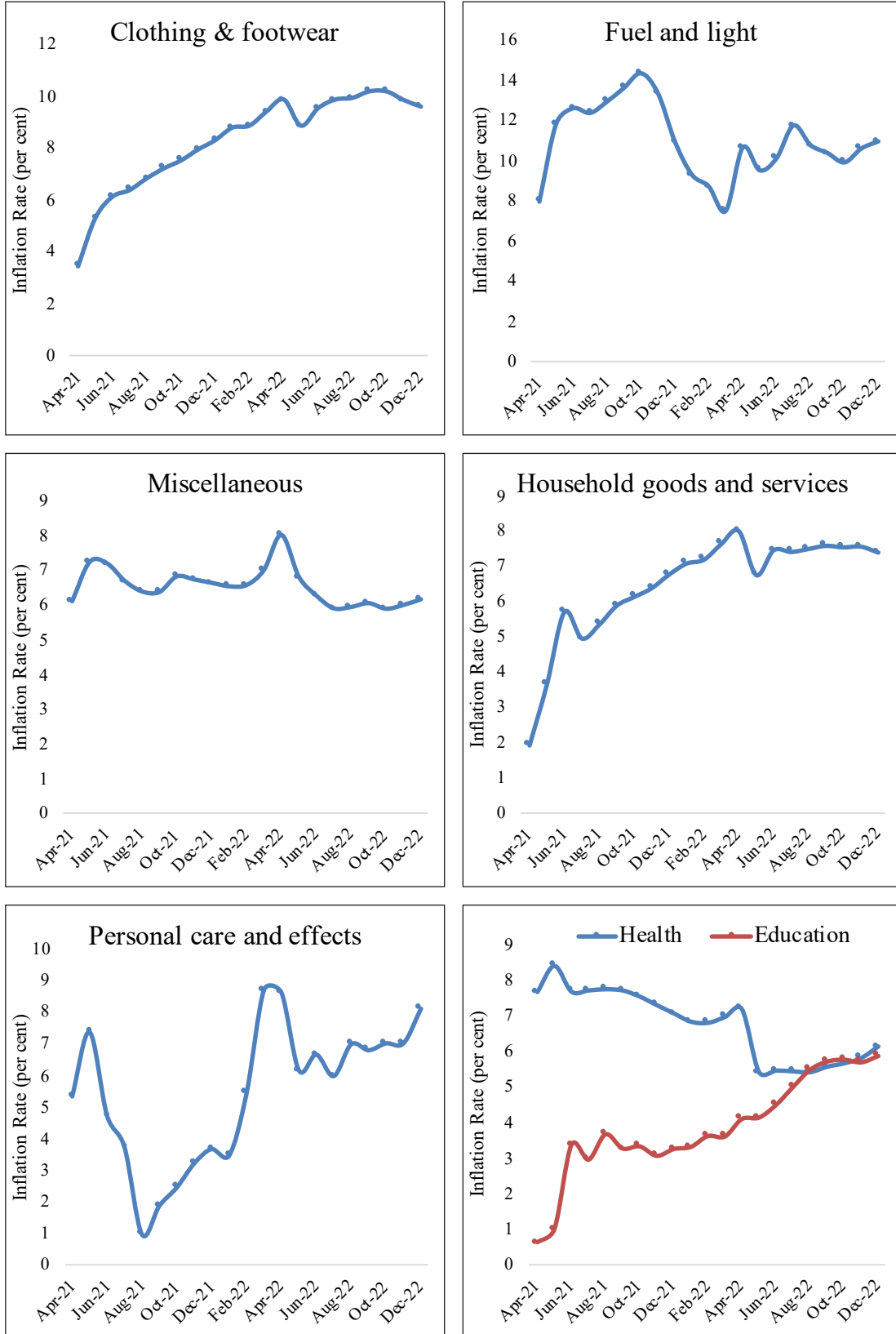
टिप्पणी: *अप्रैल-दिसम्बर

वित्त वर्ष 23 में सब्जी और अनाजों के कारण हुई खाद्य मुद्रास्फीति

5.11 वित्त वर्ष 22 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 7.0 प्रतिशत हो गई। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का आधार व्यापक है, तथापि इसमें सब्जियां, अनाज, दूध और मसालों आदि द्वारा प्रमुख योगदान दिया जाता है। आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट भविष्य में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। सितंबर, 2022 से अनाज में दो अंकों की मुद्रास्फीति देखी गई। सरकार ने एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ और चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूँ उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है और चावल पर निर्यात शुल्क लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कमजोर वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों से बचाने के लिए 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों हेतु निशुल्क अनाज वितरण करने के लिए 1 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक नई समेकित खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है।

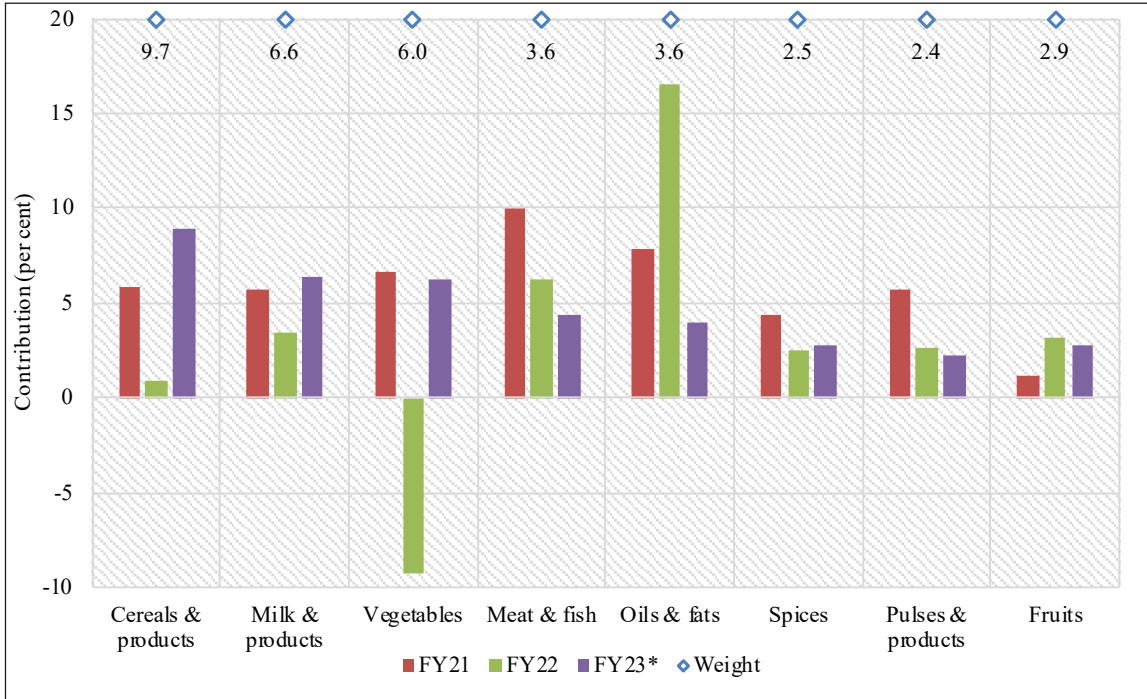
2 मौद्रिक नीति रिपोर्ट, आरबीआई, सितंबर 2022

चित्र V.5: प्रमुख समूहों/उप-समूहों में खुदरा मुद्रास्फीति



स्रोत: एमओएसपीआई

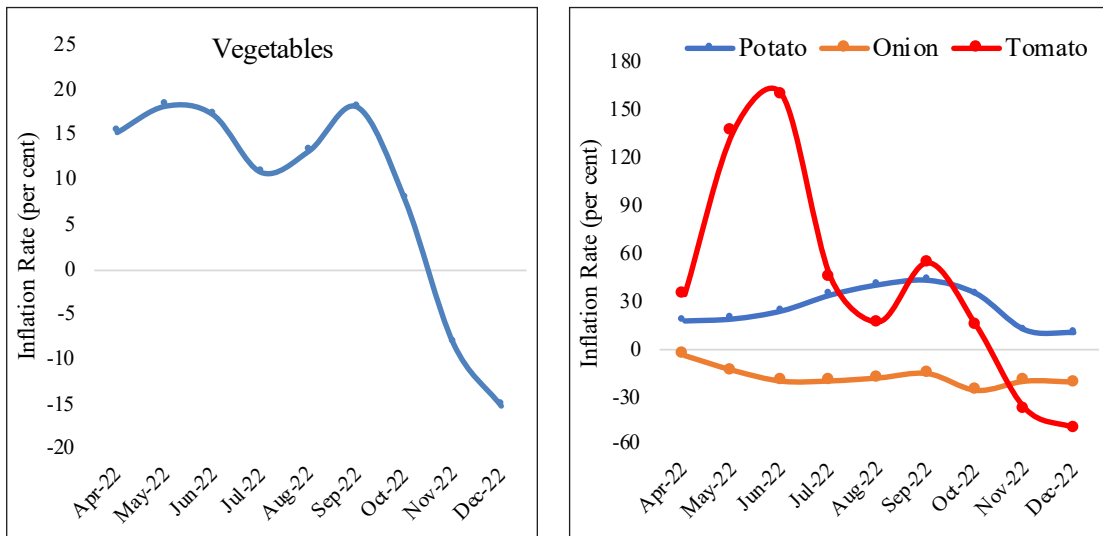
चित्र V.6: वित्त वर्ष 23 में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रेरक - सब्जियां, अनाज, दूध और मसाले



स्रोत: एमओएसपीआई
टिप्पणी: *अप्रैल-दिसम्बर

5.12 अप्रैल से सितंबर, 2022 तक सब्जियों में उच्च मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम भारी बारिश के कारण फसल की क्षति और आपूर्ति बाधित होने के कारण टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

चित्र V.7: वित्त वर्ष 23 में टमाटर की कीमत और 'सब्जियों' की मुद्रास्फीति में उछाल

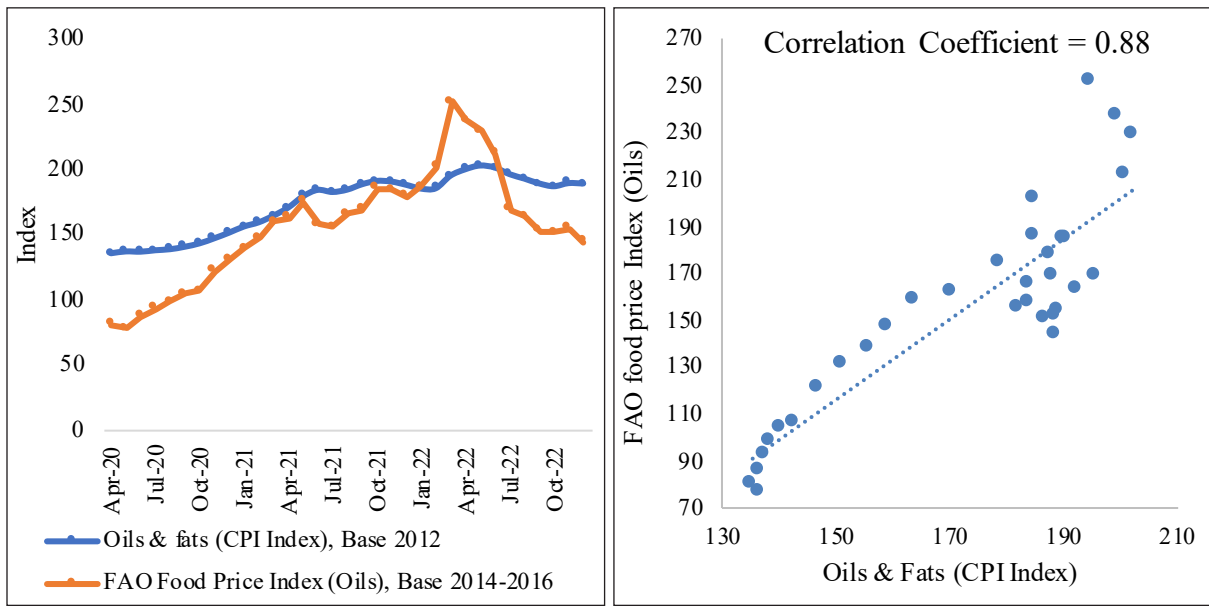


स्रोत: एमओएसपीआई

5.13 उच्च उत्पादन और बफर स्टॉक बनाए रखने और दालों पर आयात शुल्क और उपकर में कमी के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण दालों की मुद्रास्फीति अप्रभावित रही।

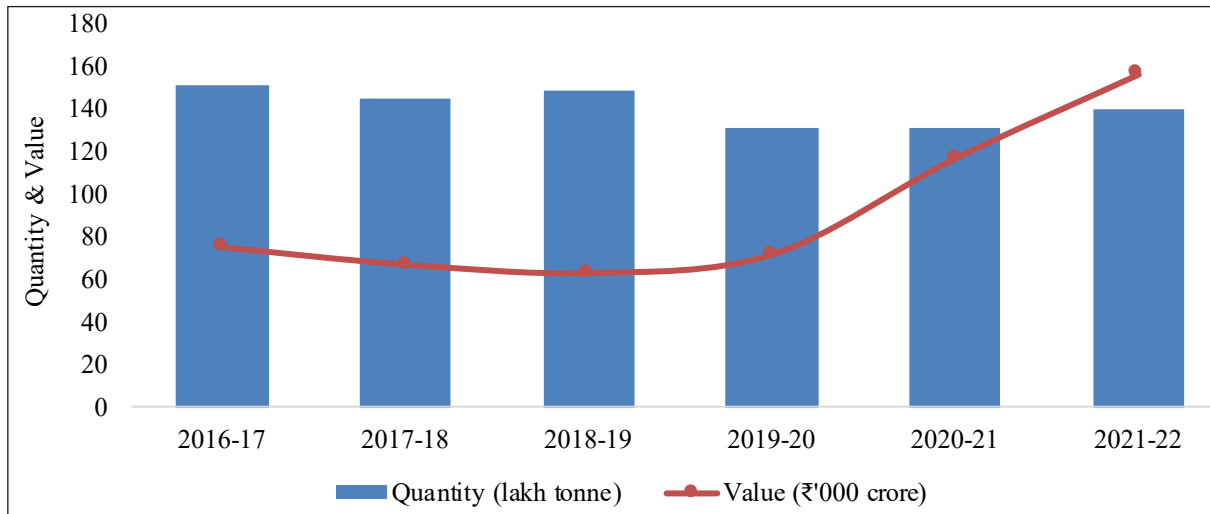
5.14 वैश्विक उत्पादन में कमी और विभिन्न देशों द्वारा निर्यात कर वसूलने में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 22 में खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं। भारत अपने खाद्य तेलों की 60 प्रतिशत मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिससे यह कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, सूरजमुखी का तेल, जो हमारे कुल खाद्य तेल आयात का 15 प्रतिशत है, मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से खरीदा जाता है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 22 ने अंतरराष्ट्रीय मूल्य दबावों के कारण खाद्य तेल की मुद्रास्फीति देखी। तथापि, टैरिफ के युक्तिकरण और खाद्य तेलों तथा तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करने के कारण वित्त वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति कम रही।

चित्र V.8: खाद्य तेलों में आयातित मुद्रास्फीति



स्रोत: एफएओ और एमओएसपीआई

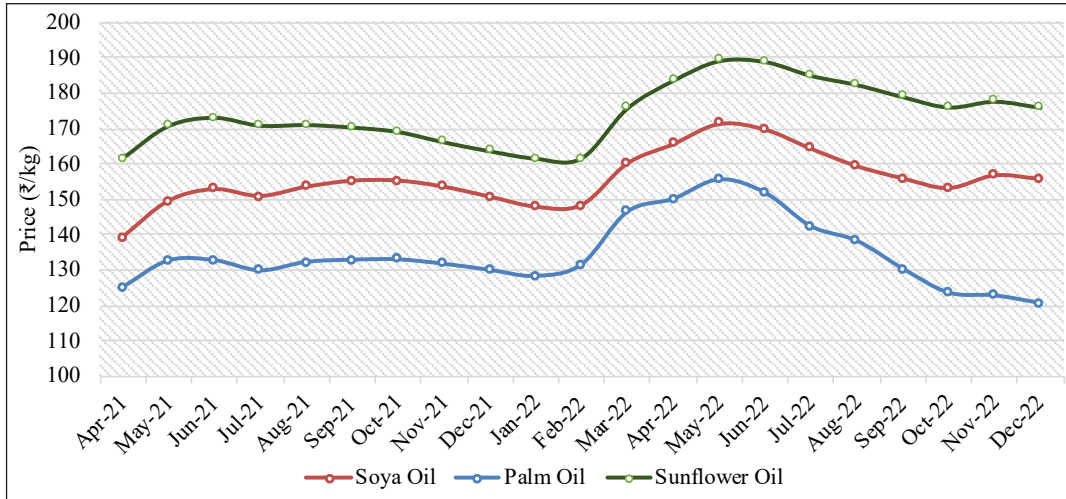
चित्र V.9: खाद्य तेलों का आयात



स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

नोट: तेल वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) के अनुरूप डाटा

चित्र V.10: खाद्य तेलों की संयत खुदरा कीमत



स्रोत: डीओसीए

बॉक्स V.1: आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति और सचिवों की समिति के द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए निम्नलिखित राजकोषीय उपाय किए गए हैं:

अनाज

- घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए 13 मई, 2022 को गेहूँ के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- 12 जुलाई, 2022 से गेहूँ के आटे के निर्यात की अनुमति दी गई थी लेकिन अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों के अधीन थे।
- 14 अगस्त, 2022 से मैदा और सूजी के निर्यात को अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी के बाद ही अनुमति दी गई थी।
- दिनांक 27 अगस्त 2022 की अधिसूचना ने गेहूँ या मेसलिन आटा (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), साबुत आटा और परिणामी आटा (एचएस कोड 1101) के निर्यात पर रोक लगा दी है। नीति में इस संशोधन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश में गेहूँ के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना है।
- 9 सितंबर 2022 से प्रभावी केंद्र सरकार चावल, ब्राउन राइस और सेमी-मिल्ड के साथ-साथ परबोल्ड राइस को छोड़कर पूरी तरह मिल्ड राइस पर 20 फीसदी का निर्यात शुल्क लगाया।

दलहन

- 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में मूल्य स्थिरीकरण के लिए दालों का बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। बफर स्टॉक से दालों के कैलिब्रेटेड रिलीज से बाजार कीमतों में संतुलन आयेगा।
- 26 जुलाई, 2021 से मसूर पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, 12 फरवरी, 2022 से मसूर पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को शून्य प्रतिशत पर लाया गया था। एआईडीसी की शून्य दर को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- 30 मार्च, 2022 को मुक्त श्रेणी के तहत तुअर और उड़द का आयात 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

- 1 सितंबर, 2022 को केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1.5 मिलियन टन चना रियायती दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया। राज्य अपने संबंधित निर्गम मूल्य पर 8 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर चना खरीद सकेंगे।

खाद्य तेल

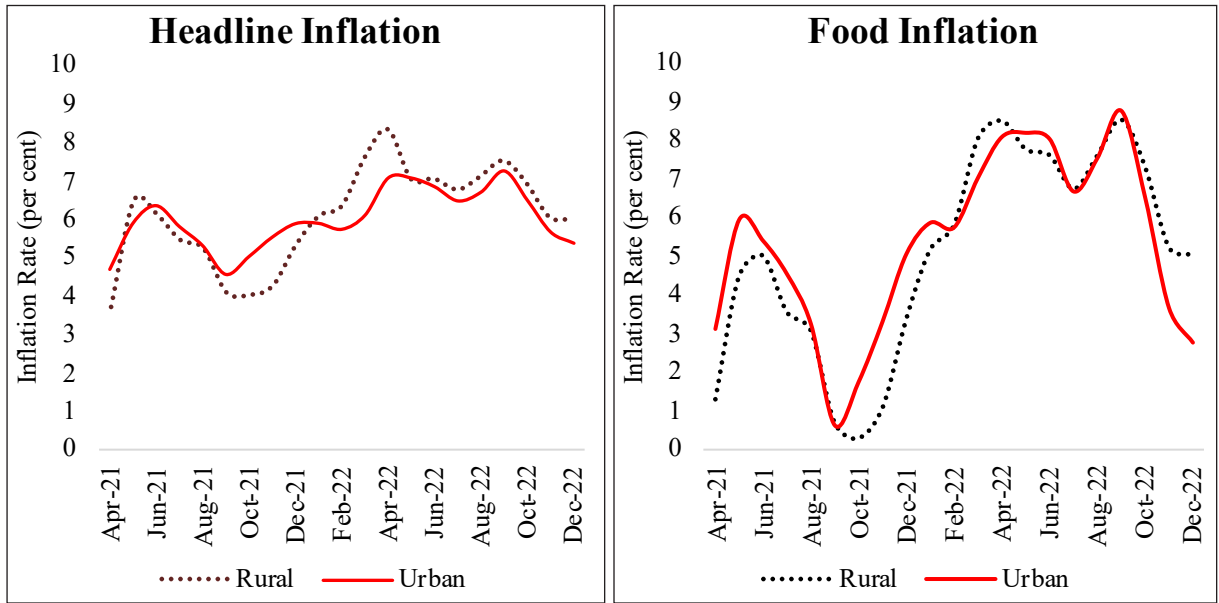
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 24 मई, 2022 को कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल, प्रत्येक के 20 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक आयात पर सीमा शुल्क और एआईडीसी को छूट दी।
- 21 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक रिफाइंड पाम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 17.5 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी और 13 फरवरी, 2022 से 30 सितंबर 2022 तक क्रूड पाम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक रिफाइंड पाम ऑयल के मुफ्त आयात की अनुमति दी है।
- केंद्र सरकार ने नवंबर, 2021 में क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 2.5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी थी। इन तेलों पर कृषि उपकरण को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क को मौजूदा 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सोया मील की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। सोया मील पर 23 दिसंबर, 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए स्टॉक सीमा लगाई गई है।
- सभी खाद्य तेलों और तिलहनों पर लगाई गई स्टॉक सीमा को दिनांक 3 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा और आवाजाही पर प्रतिबंध आदेश, 2016 में संशोधन करके 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस उपाय से बाजार में जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसी किसी भी अनुचित प्रथा पर अंकुश लगा और इससे खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली।
- जुलाई, 2022 में, केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य में ₹15 प्रति लीटर की कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्र द्वारा खाद्य तेल कंपनियों को वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के निर्देश के बाद मद्र डेयरी ने चावल की भूसी और सोयाबीन तेल की कीमतों में ₹14 प्रति लीटर तक की कमी की है।

ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में अंतर कम हुआ है

5.15 महामारी के वर्षों के दौरान देखी गई प्रवृत्ति से विपरीत, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष से ऊपर रही। सीपीआई-सी आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2022 में 8.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद वैश्विक खाद्य कीमतों में सुधार और कृषि इनपुट लागत में कमी के कारण गिरावट आई है। तथापि, शहरी मुद्रास्फीति के लिए राहत अधिक स्पष्ट थी, जो दिसंबर, 2022 में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण ईंधन मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष की तुलना में कम रही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के विपरीत जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन की कीमतों पर दबाव कम रहा।

5.16 जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर कम हो रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 22 में दोनों के बीच व्यापक अंतर देखा गया था। खाद्य मुद्रास्फीति में अंतर के कारण मार्च, 2022 में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच का अंतर अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुँच गया। भीतरी इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में इस समय के दौरान सब्जियों और तेलों की खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।

चित्र V.11: शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति

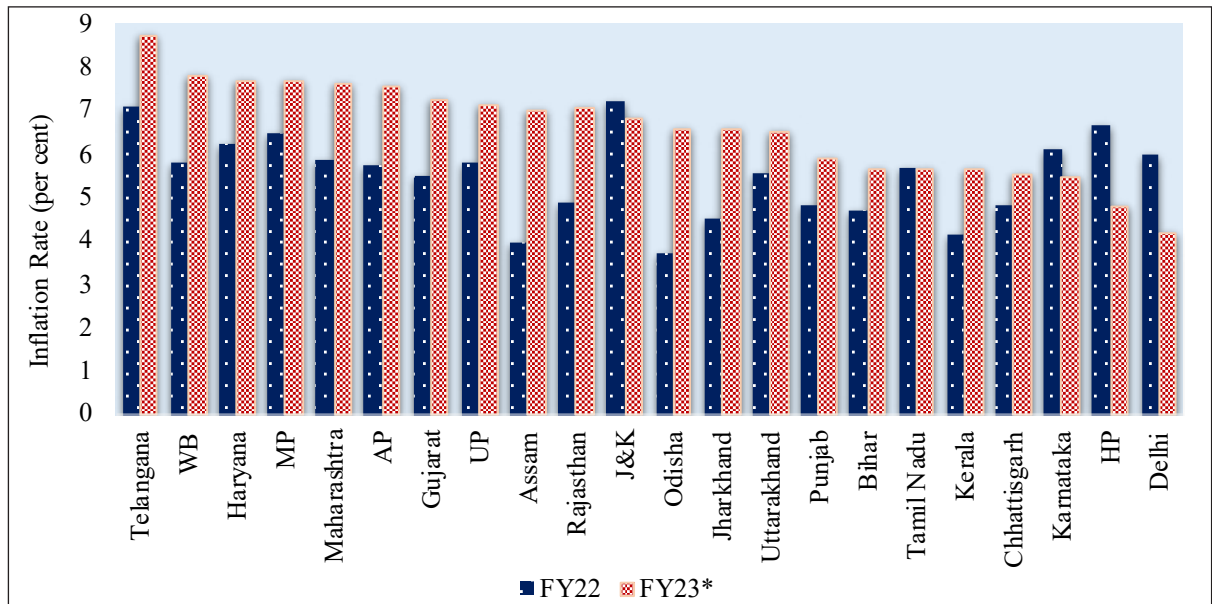


स्रोत : एमओएसपीआई

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी मुद्रास्फीति से ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक है

5.17 वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 में अधिकांश राज्यों के सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 23 में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से मुद्रास्फीति की उच्च दर देखी गई। मुद्रास्फीति वृद्धि में ईंधन और कपड़े का प्रमुख योगदान था।

चित्र V.12: वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति



स्रोत: एमओएसपीआई

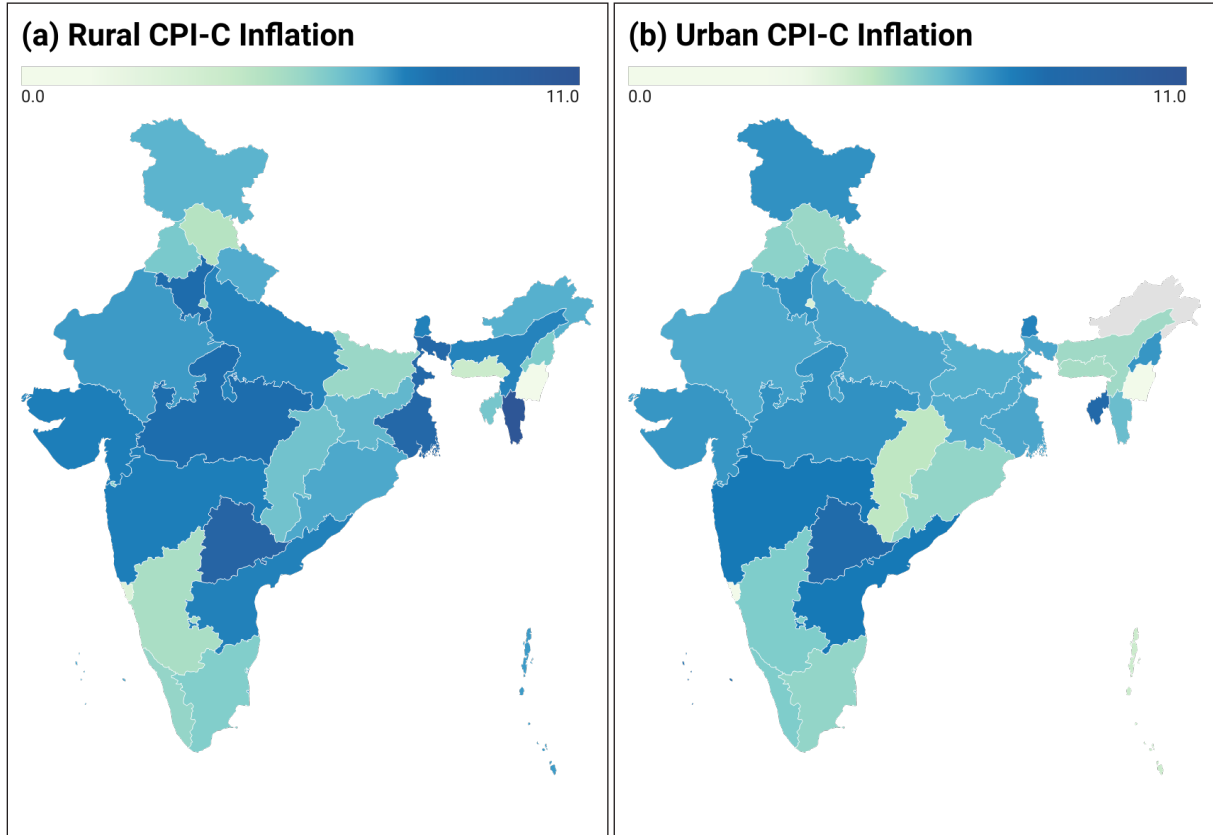
टिप्पणी: (i) *अप्रैल-दिसम्बर

(ii) कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल और मई, 2020 के महीनों के लिए सूचकांकों की अनुपलब्धता के कारण वित्त वर्ष 22 की मुद्रास्फीति जून, 2021 से मार्च, 2022 के औसत पर आधारित है।

(iii) 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 22 प्रमुख राज्यों को दर्शाया गया है

5.18 अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान वर्ष में शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक देखी गई है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई है। असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक रही। हरियाणा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में यह इसलिए अधिक थी क्योंकि वहाँ 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'कपड़े और जूते' से संबंधित मुद्रास्फीति अधिक है। मध्य प्रदेश, मणिपुर और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में, यह 'ईंधन और प्रकाश' खंडों के कारण हुआ था। बिहार, मेघालय और त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति के लिए भोजन, कपड़े और ईंधन का प्रमुख योगदान था।

चित्र V.13: वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर ग्रामीण मुद्रास्फीति



स्रोत: एमओएसपीआई

टिप्पणी: (i) *अप्रैल- दिसम्बर

(ii) शहरी अरुणाचल प्रदेश के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

घरेलू थोक मूल्य मुद्रास्फीति

वैश्विक आपूर्ति व्यवधान के कारण हुई थोक मूल्य मुद्रास्फीति

5.19 कोविड-19 की अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति कम रही, और महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक कार्यकलापों के फिर से शुरू होने पर इसमें पुनः तेजी आने लगी। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने इस बोज़ को और बढ़ा दिया क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बिगड़ गईं। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति की दर लगभग 13.0 प्रतिशत तक बढ़ गई। पेट्रोलियम उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की कीमतें, अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के अधिकतम जोखिम सहित घरेलू थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि के रूप में परिवर्तित हुए हैं।

सारणी V.2: डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत) के आधार पर औसतन वार्षिक थोक मुद्रास्फीति (आधार: 2011-12=100

समूह/उप-समूह	भार	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23*
प्राथमिक सामग्री	22.6	6.8	1.7	10.3	12.3
खाद्य सामग्री	15.3	8.4	3.1	4.1	8.3
अनाज	2.8	7.5	-2.6	1.6	10.7
दाल	0.6	15.9	11.6	6.9	0.0
सब्जियाँ	1.9	31.2	3.4	0.4	13.2
फल	1.6	3.2	1.4	11.3	10.4
गैर-खाद्य सामग्री	4.1	4.5	1.4	21.1	12.0
खनिज पदार्थ	0.8	13.2	6.7	19.6	6.2
कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2.4	-7.7	-17.5	56.7	57.7
ईंधन और विद्युत	13.2	-1.8	-8.0	32.6	33.8
एलपीजी	0.6	-8.3	-2.7	43.3	16.9
पेट्रोल	1.6	-3.2	-11.8	62.9	41.9
हाई स्पीड डीजल	3.1	-3.5	-14.4	59.9	60.8
विनिर्मित उत्पाद	64.2	0.3	2.7	11.1	7.1
खाद्य उत्पाद	9.1	4.1	5.6	11.7	6.0
खाद्य तेल	2.6	1.4	20.3	30.5	1.4
खाद्य मुद्रास्फीति (खाद्य सामग्री + खाद्य उत्पाद)	24.4	6.9	3.9	6.8	7.5
मूल मुद्रास्फीति (निर्मित उत्पाद-खाद्य उत्पाद)	55.1	-0.4	2.2	11.0	9.2
मुख्य मुद्रास्फीति	100	1.7	1.3	13.0	11.5

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

टिप्पणी: *अप्रैल-दिसंबर 2022, नवंबर और दिसंबर, 2022 के आकड़े अनंतिम हैं।

5.20 वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान डब्ल्यूपीआई में दो अंकों की मुद्रास्फीति के लिए खाद्य मुद्रास्फीति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो वित्त वर्ष 22 में 6.8 प्रतिशत की तुलना में 7.5 प्रतिशत पर रही। अनियमित जलवायु परिस्थिति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में अनाज और सब्जियों का प्रमुख योगदान था। वित्त वर्ष 23 में 'विनिर्माण उत्पाद' उपसमूह में मुद्रास्फीति में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण इनपुट पर शुल्कों के युक्तिकरण और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण काफी गिरावट देखी गई। वित्त वर्ष 22 की तुलना में, वित्त वर्ष 23 में मूल मुद्रास्फीति कम रही।

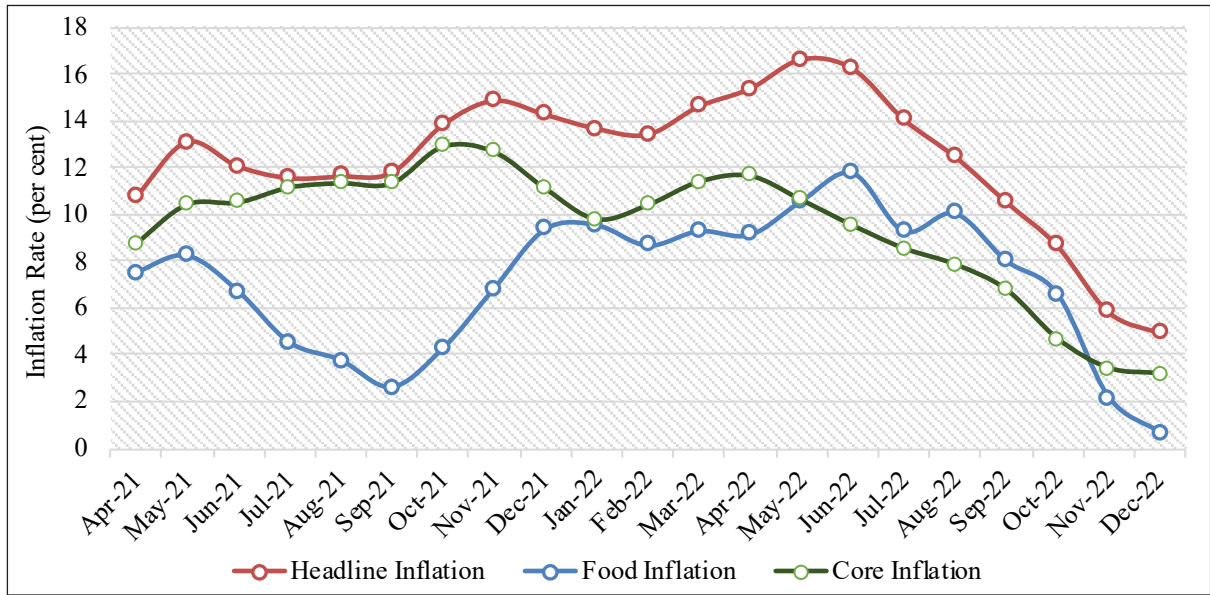
5.21 समग्र रूप से, थोक मूल्य मुद्रास्फीति की मासिक प्रवृत्ति अपने चरम 16.6 प्रतिशत से नीचे की ओर गिरी है, सितंबर, 2022 में 10.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गई है। डब्ल्यूपीआई के सभी तीन उपसमूहों के मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई थी।

5.22 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का एक भाग आयातित मुद्रास्फीति है। खाद्य तेलों पर उच्च आयात निर्भरता का अर्थ है कि इन उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अस्थायी प्रभाव घरेलू कीमतों में भी परिलक्षित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन³ में दर्शाया गया है कि वैश्विक

3 मौद्रिक नीति रिपोर्ट, आरबीआई, सितंबर 2022

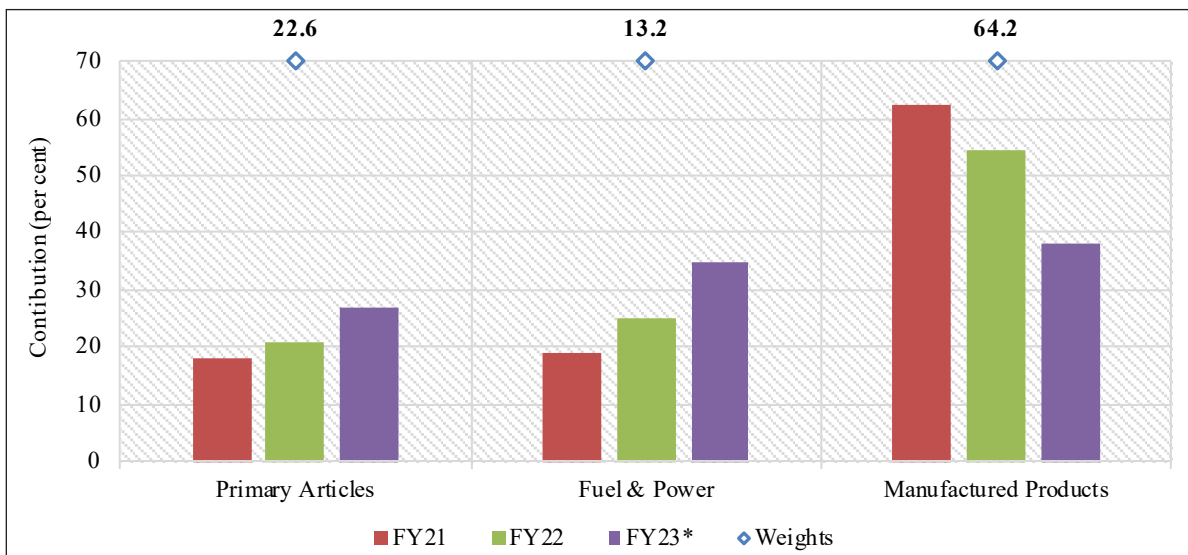
मुद्रास्फीति के झटके के कारण सभी देशों और क्षेत्रों में कीमतों में एक प्रतिशत की वृद्धि भारत में मुद्रास्फीति को लगभग 63 आधार अंकों तक बढ़ा सकती है, जिसमें 100 आधार अंकों के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त घरेलू अप्रत्यक्ष प्रभाव (46 आधार अंक) और वैश्विक प्रभाव (17 आधार अंक) शामिल हैं। डबल्यूपीआई (विनिर्माण घटक) पर विश्व बाजारों में कीमतों का प्रभाव विशेष रूप से तेल और बुनियादी धातुओं की कीमतों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वर्तमान वित्त वर्ष में खाद्य तेल, रबर, कपास, कच्चा तेल और धातुओं की वैश्विक कीमतों में कमी आई है। वित्त वर्ष 23 के प्रथम छमाही में पूंजी के बहिर्प्रवाह ने भारत की विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, यह आयातित इनपुट की उच्च कीमतों का एक और कारण था, जो ज्यादातर डॉलर आधारित होता है।

चित्र V.14: मूल और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट



स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

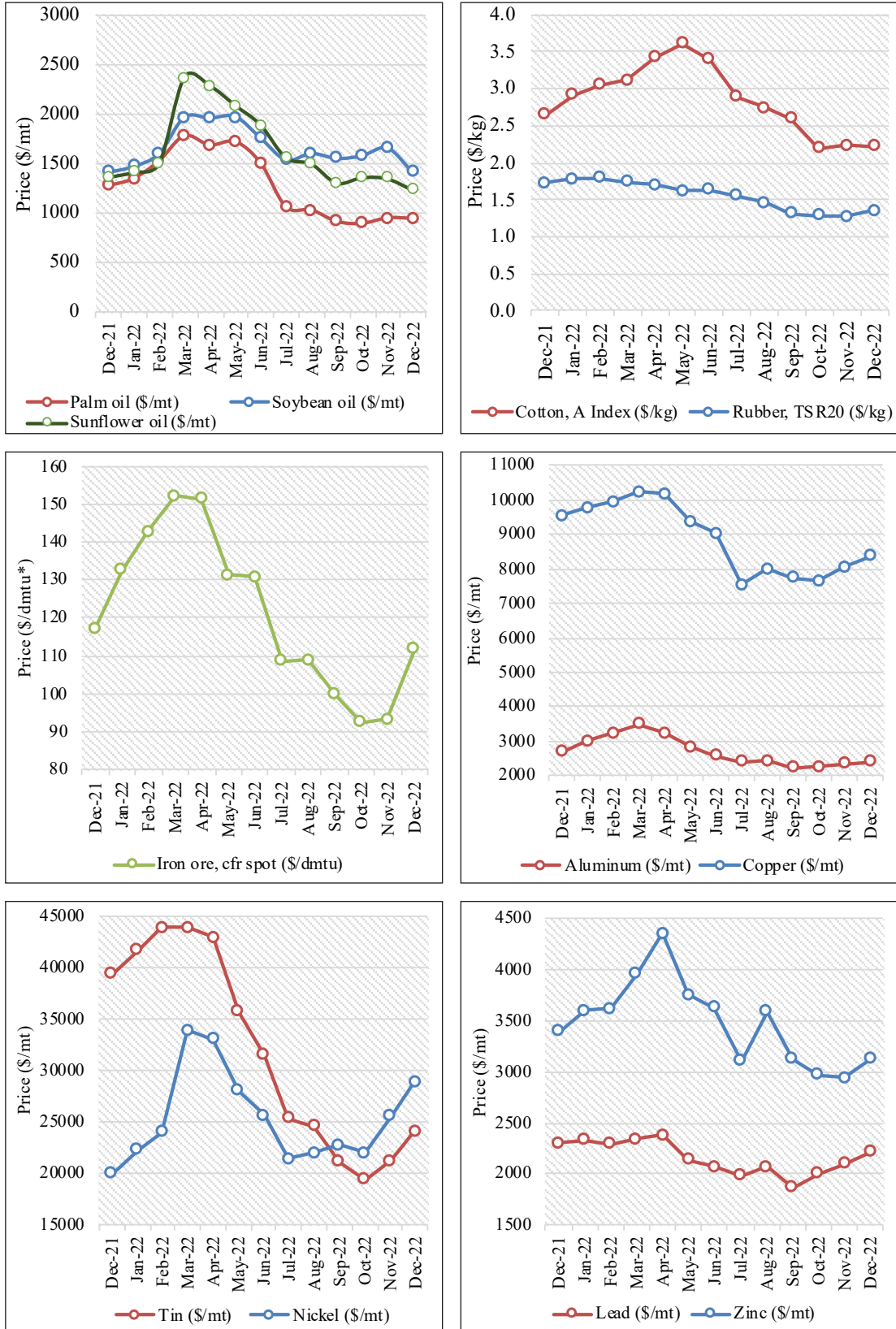
चित्र V.15: वित्त वर्ष 23* में थोक मुद्रास्फीति के प्रेरक - “प्राथमिक सामग्री” और “ईंधन और विद्युत”



स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

टिप्पणी: *अप्रैल-दिसंबर

चित्र V.16: वैश्विक वस्तु कीमतों में कमी



स्रोत: पिंग शीट, विश्व बैंक

टिप्पणी: *डीएमटीयू: शुष्क मीट्रिक टन इकाई

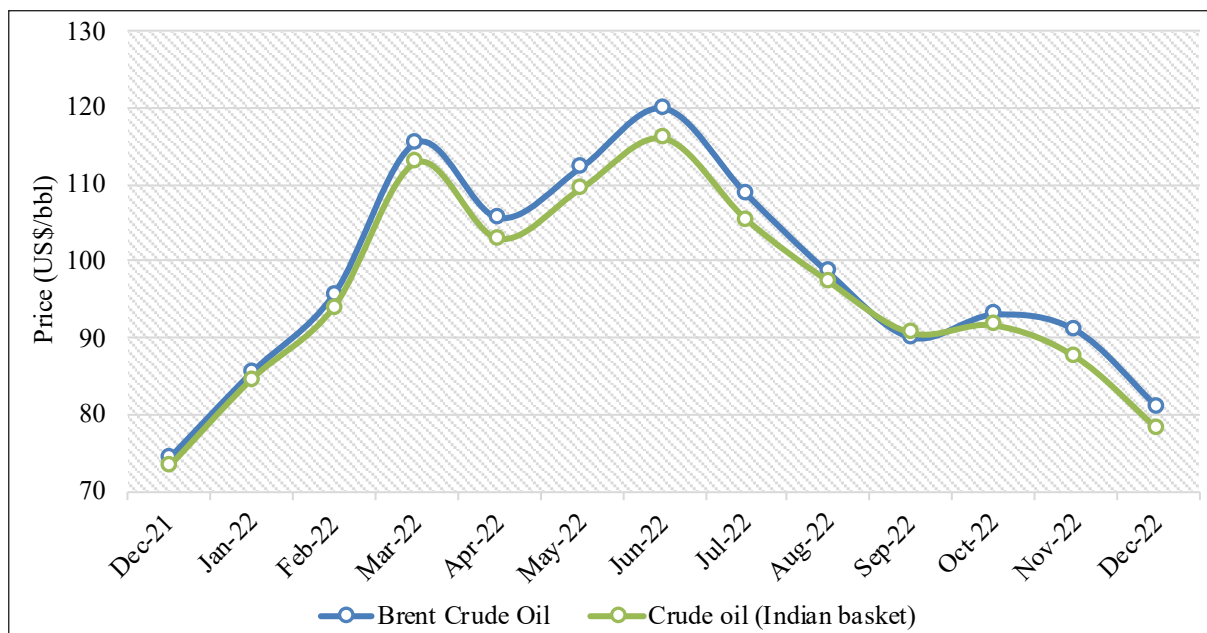
बॉक्स V.2: इनपुट कीमतों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

- **ईंधन की कीमतें:** केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को समायोजित करके हस्तक्षेप किया है। पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹10 की कटौती का पहला चरण दिनांक 4 नवंबर, 2021 से और दूसरा चरण दिनांक 22 मई, 2022 से प्रभावी किया गया था (पेट्रोल पर ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर)।
- **प्लास्टिक उत्पाद:** घरेलू विनिर्माण की लागत को कम करने के लिए प्लास्टिक उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। दिनांक 21 मई, 2022 को नाफ्था, प्रोपलीन ऑक्साइड और पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड पर शुल्क क्रमशः 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **इस्पात:** दिनांक 21 मई 2022 को, प्रमुख इनपुट - फेरोनिकेल, कोकिंग कोल, पीसीआई कोल - पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कोक और सेमी-कोक पर शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट के निर्यात पर कर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि लौह छर्चों पर कर को बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **कपास:** सरकार ने दिनांक 14 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था, ताकि वस्त्र उद्योग को लाभ हो सके और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इससे पहले, कपास के आयात पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 प्रतिशत एआईडीसी लगाया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया था।
- **हीरे और रत्न:** बजट 2022-2023 में, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था और साधारण रूप से काटे गए हीरे पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया था।
- **रसायनिक उत्पाद:** बजट 2022-23 में पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण रसायनों जैसे मेथनॉल, एसिटिक एसिड और भारी फीडस्टॉक्स पर सीमा शुल्क घटाया गया था।

ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति: वैश्विक कच्चे तेल की घटती कीमत

5.23 वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में, डबल्यूपीआई 'ईंधन और विद्युत' में मुद्रास्फीति ज्यादातर उच्च अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से प्रेरित थी। कोविड-19 में प्रतिबंधों के कारण वैश्विक मांग में कमी के प्रत्युत्तर में, वित्त वर्ष 21 के दौरान कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत 20-65 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल की सीमा में रही। तत्पश्चात् पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और अन्य तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति में अभूतपूर्व कटौती के कारण कीमतें बढ़ने लगीं। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में रुझान बढ़ोत्तरी की ओर जारी रहा, क्योंकि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में कोविड -19 प्रतिबंधों में छूट सहित मांग में बढ़ोत्तरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, जून 2022 में पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आपूर्ति में व्यवधान के कारण, कच्चे तेल की भारतीय बास्केट 116 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल पर पहुंच गई। इसके बाद, दिसंबर, 2022 में कीमत गिरकर 78 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल हो गई। इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2021 और मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कमी आई।

चित्र V.17: कच्चे तेल की कीमतों में कमी



स्रोत: पिक शीट, विश्व बैंक और पीपीएसी, एमओपीएनजी

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति का अभिसरण

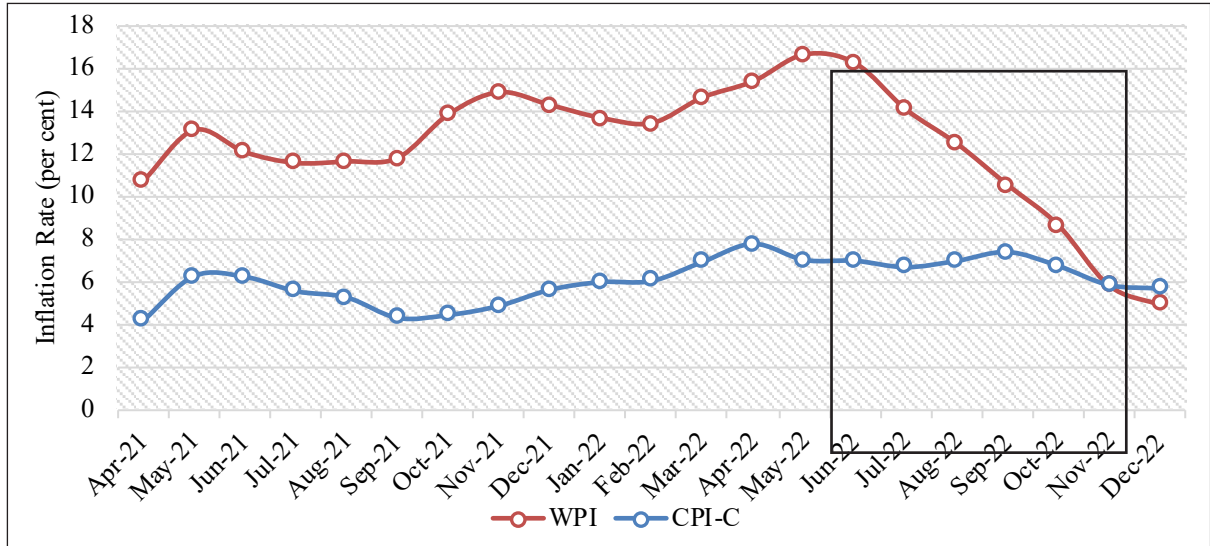
5.24 महामारी के प्रकोप के बाद से भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित हुई है। जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का थोक मूल्यों पर प्रभाव अपेक्षाकृत जल्दी होता है, यह खुदरा कीमतों को एक अंतराल के साथ प्रभावित करता है। यह डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति दरों के बीच अंतर उत्पन्न करता है। यह दो सूचकांकों में अलग-अलग सूचकांक को सौंपी गई संरचना और भार में अंतर के कारण भी है।

5.25 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-सी पर आधारित मुख्य मुद्रास्फीति मार्च, 2021 में विभाजित होने लगी, क्योंकि डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति प्रतिकूल आधारित प्रभावों के कारण दोहरे अंकों में पहुंच गई, जबकि सीपीआई-सी मुद्रास्फीति स्थिर रही। नवंबर, 2021 में 10 प्रतिशत के अपने चरम स्तर पर पहुंचने से पहले सीपीआई-सी और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का अंतर बढ़ता रहा। इसके बाद, अप्रैल 2022 तक अंतर कम होना शुरू हो गया। हालांकि, अभिसरण का मार्ग अल्पकालिक था क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप फरवरी 2022 में एक और मुद्रास्फीति दबाव शुरू होने लगा था। सूचकांक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती मांग का नुकसान 2 महीने के छोटे अंतराल सहित डब्ल्यूपीआई में परिलक्षित हुआ। इसके परिणामस्वरूप, मई, 2022 में मुद्रास्फीति के दो संकेतक फिर से अलग होने लगे। तेल सहित वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने और अनुकूल मौनसून, टीकाकरण की अगुवाई वाली आर्थिक बहाली आदि जैसे मजबूत सहायक घरेलू कारकों के प्रभावों के बाद ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह कमी उसको संकुचित करने लगी और 21 महीने के पश्चात नवंबर, 2022 में समाप्त हो गई। इसने खुदरा क्षेत्र की उच्च निविष्टि लागतों के निकटतम निकासी के पूरा होने का भी संकेत दिया।

5.26 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई सूचकांकों के बीच अभिसरण मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित था। सबसे पहले, कच्चा ईंधन, लोहा, एल्यूमीनियम और कपास जैसी वस्तुओं की मुद्रास्फीति में कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक कम हुआ। सीपीआई की तुलना में ये वस्तुएं डब्ल्यूपीआई में अधिक भार रखती हैं। इसके अतिरिक्त, ये

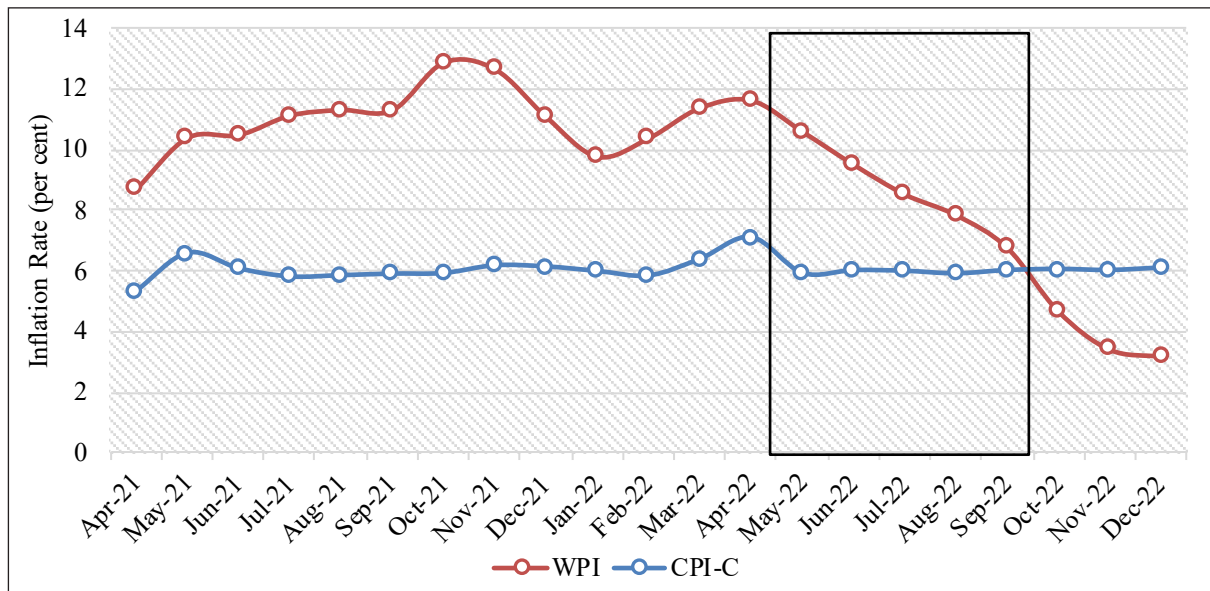
वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और थोक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा इनका गहनता से उपयोग किया जाता है। इन पण्यों की कीमतों में कमी आने से मुद्रास्फीति के दोनों माप नजदीक आने लगे। दूसरा, सीपीआई मुद्रास्फीति सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी। सेवाएँ सीपीआई-सी के मुख्य घटक का हिस्सा हैं, परंतु यह डबल्यूपीआई बास्केट में शामिल नहीं हैं।

चित्र V.18: प्रमुख डबल्यूपीआई की मुद्रास्फीति सहित मुख्य सीपीआई- मुद्रास्फीति अभिसरण



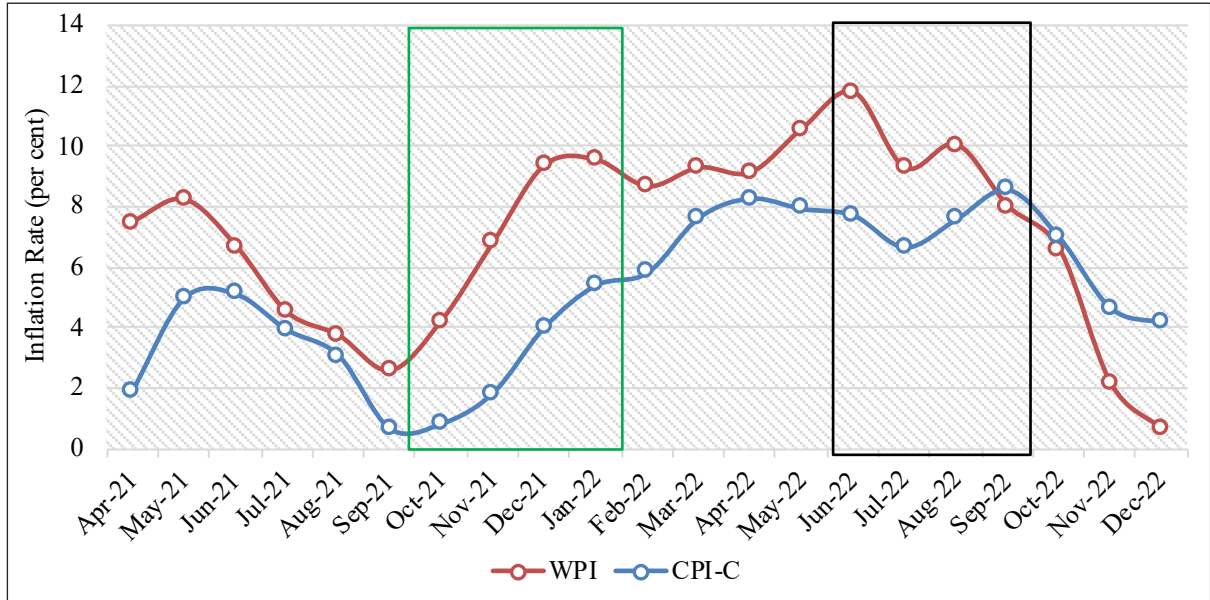
स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.19: मूल मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डबल्यूपीआई



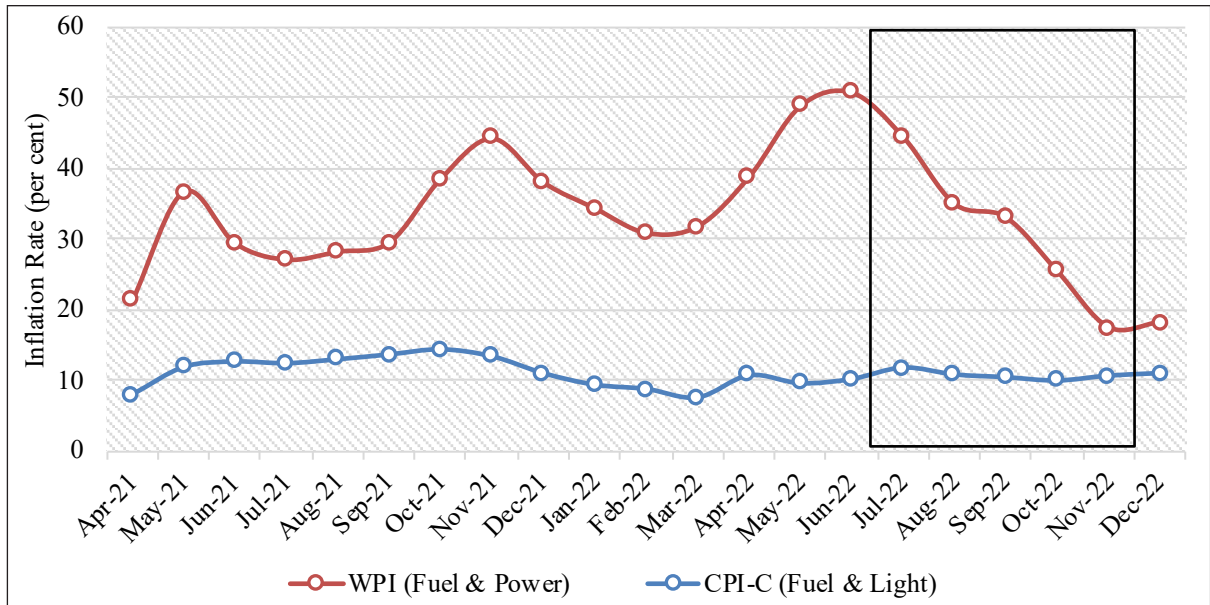
स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.20: खाद्य मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डब्ल्यूपीआई



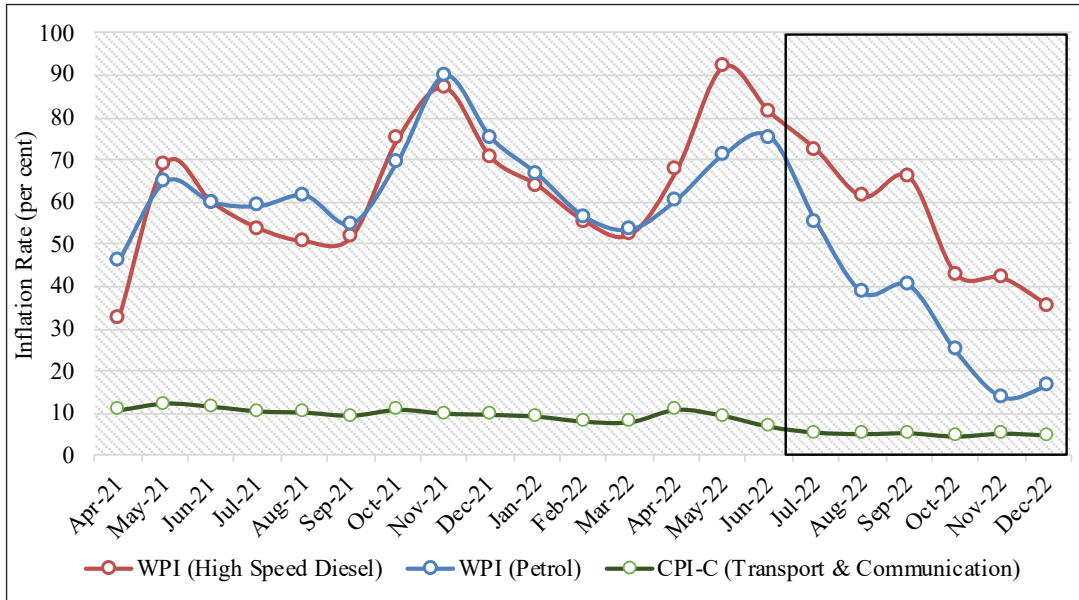
स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.21: सीपीआई (ईंधन और विद्युत) और डब्ल्यूपीआई (ईंधन और बिजली) के बीच मुद्रास्फीति दरों का अभिसरण



स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.22: खुदरा और थोक ऊर्जा मुद्रास्फीति दरों में अभिसरण

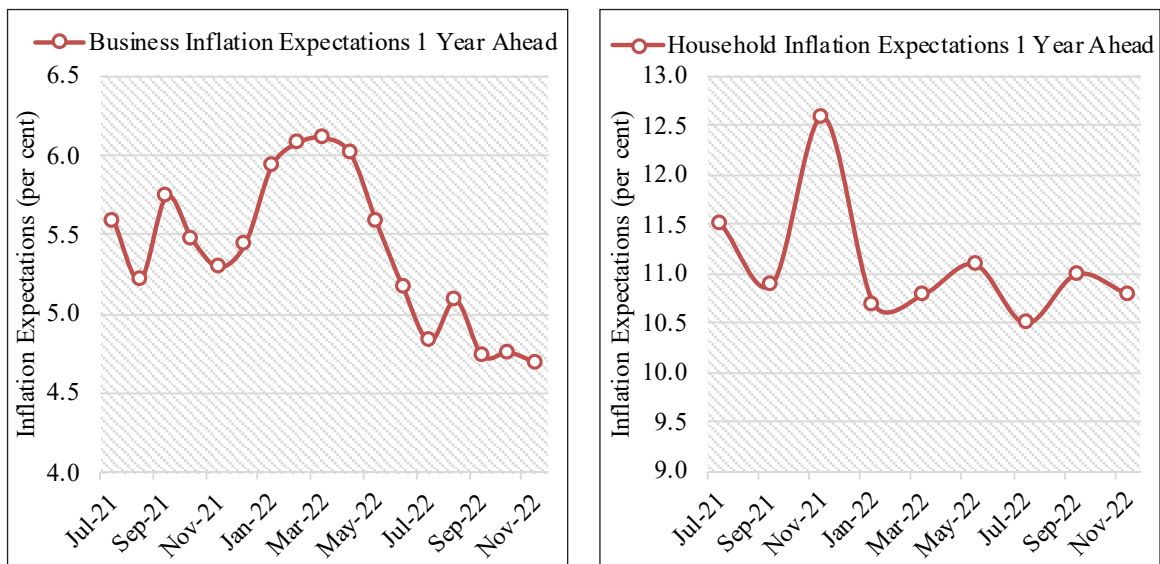


स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

मुद्रास्फीतिक संभावनाओं में गिरावट

5.27 मुद्रास्फीति को रेखांकित करने में मुद्रास्फीतिक संभावनाएं निर्णायक हैं। आरबीआई ने अपने भावी मार्गदर्शन और उत्तरदायी मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति संभावनाओं की एंकरिंग करके देश की मुद्रास्फीति के प्रक्षेप-पथ के मार्गदर्शन में मदद की है। व्यवसायों द्वारा आगामी वर्ष की मुद्रास्फीतिक संभावनाओं ने वर्तमान वित्त वर्ष में घटती प्रवृत्ति दर्शायी है। जैसा कि व्यवसाय मूल्य निर्धारित करता हैं, मुद्रास्फीति पर उनकी धारणा यह समझने में महत्वपूर्ण है कि क्या लागत को पारित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में कीमतें अधिक होंगी। इसी तरह, परिवारों द्वारा मुद्रास्फीतिक संभावनाओं - जो अर्थव्यवस्था के मूल्य स्वीकारकर्ता हैं- निकट भविष्य में उनके उपभोग विकल्पों का निर्धारण करते हैं। कारोबारों की तरह घरेलू महंगाई की संभावना में भी कमी आई है।

चित्र V.23: व्यापार और घरेलू मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं कम हो रही हैं



स्रोत: आईआईएम-ए और आरबीआई

मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीतिगत उपाय

5.28 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मई और दिसंबर, 2022 के बीच नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 2.25 प्रतिशत (225 आधार अंक) बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया।

सारणी V.3: मौद्रिक नीति संबंधी विवरण- सख्त मौद्रिक नीति

एमपीसी विवरण की तारीख	एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन
8 अप्रैल, 2022	4 प्रतिशत पर यथावत
4 मई, 2022	4.0 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत (40 आधार अंक)
8 जून, 2022	4.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.9 प्रतिशत (50 आधार अंक)
5 अगस्त, 2022	4.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत (50 आधार अंक)
30 सितंबर, 2022	5.4 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत (50 आधार अंक)
7 दिसंबर 2022	5.9 प्रतिशत से बढ़कर 6.25 प्रतिशत (35 आधार अंक)

स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स V.3: वर्तमान मुद्रास्फीति 1970 के दशक से किस प्रकार भिन्न है?

वर्तमान वर्ष में अभूतपूर्व वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 1970 के दशक के अनुभव को दोहराती है, विशेष रूप से वर्ष 1973 और वर्ष 1979 में तेल संकट के बाद। दोनों संकटों ने दुनिया भर में वस्तु की कीमतों में वृद्धि और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर उनके विस्तारित प्रभाव में योगदान दिया। तथापि, संकट का वातावरण और तीव्रता विभिन्न संदर्भों में भिन्न है।

प्रथमतः हाल ही में तेल की कीमतों में बढ़ती 1970 के दशक के संकट की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है, जिसने तेल की कीमतों को ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुंचा दिया था।

द्वितीयतः 1970 के दशक के संकट के विपरीत, जो तेल की कीमतों तक ही सीमित था, हाल के संकट में वस्तुओं की विस्तृत श्रेणी में व्यापक वृद्धि देखी गई है। वर्तमान वर्ष में गैर-तेल ऊर्जा, कुछ कृषि वस्तुओं, उर्वरकों और धातुओं की कीमतें अपने पूर्व-महामारी के स्तर से काफी ऊपर बढ़ गई हैं।

तृतीयतः वस्तु आपूर्ति व्यवधानों ने 1970 के दशक की तुलना में हाल की कीमत वृद्धि में छोटी भूमिका निभाई है। पिछले एक साल में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सहित तेल के अतिरिक्त कई वस्तुओं के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है। चूंकि वर्ष 1970 के दशक की तुलना में वैश्विक वस्तु आपूर्ति श्रृंखला अब अधिक कुशल हो गई है और इसलिए, मुद्रास्फीति के दबाव को काफी आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। तथापि, आने वाले वर्ष में आपूर्ति व्यवधान तेज हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के कारण गेहूँ, मक्का और उर्वरकों के वैश्विक उत्पादन को कम करेगा, जबकि रूसी तेल और गैस पर अधिकमत मूल्य इन उत्पादों की आपूर्ति को कम कर सकती है।

चतुर्थतः वैश्विक मुद्रास्फीति, जो वर्ष 2021 की शुरुआत के बाद से काफी बढ़ गई है, कई वर्षों के निम्न मुद्रास्फीति के बाद हुआ है। इसके विपरीत, 1973 का संकट कई वर्षों की पृष्ठभूमि से लगातार बढ़ती विश्व मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदों में न मिलते मुद्दों के संकेतों के कारण हुआ था।

अंततः 1973 के संकट ने ब्रेटन वुड्स द्वारा प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के पतन का बारीकी से पालन किया गया था क्योंकि लक्ष्यों और यहाँ तक कि मौद्रिक नीति के उपकरणों को कई देशों में कमजोर तरीके से परिभाषित किया गया था। यकीनन, केंद्रीय बैंकों के पास अधिक स्पष्ट और अधिक मजबूत संस्थागत रूपरेखा हैं जो आज मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसने वर्ष 2022 के दौरान मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बावजूद जनता की मुद्रास्फीति की संभावना को अनियंत्रित होने से रोका है।

वस्तु बाजार के रूख के अलावा, ऊर्जा की ऊंची कीमतें अतीत की तुलना में आज कम मायने रखती हैं। वैश्विक केंद्रीय बैंकों के बीच बेहतर समन्वय और अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरणों के अनुप्रयोग सहित, मुद्रास्फीति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया है ताकि इसका नकारात्मक उतार-चढ़ाव सीमित और अस्थायी हो। सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता - वस्तुओं और सेवाओं की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा - 1970 के दशक के अंत से लगभग 40 प्रतिशत तक गिर गई है। साधन के लिए इनपुट बास्केट और गंतव्यों के विविधीकरण सहित, वस्तु पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है। इसलिए, हम आशा कर सकते हैं कि 1970 के दशक की तुलना में हाल की वस्तु मूल्य वृद्धि कम विघटनकारी होगी।

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और वोक्स ईयू, 2022 द्वारा वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, जून 2022

आवासन मूल्य: महामारी के बाद उभरता हुआ आवासन क्षेत्र

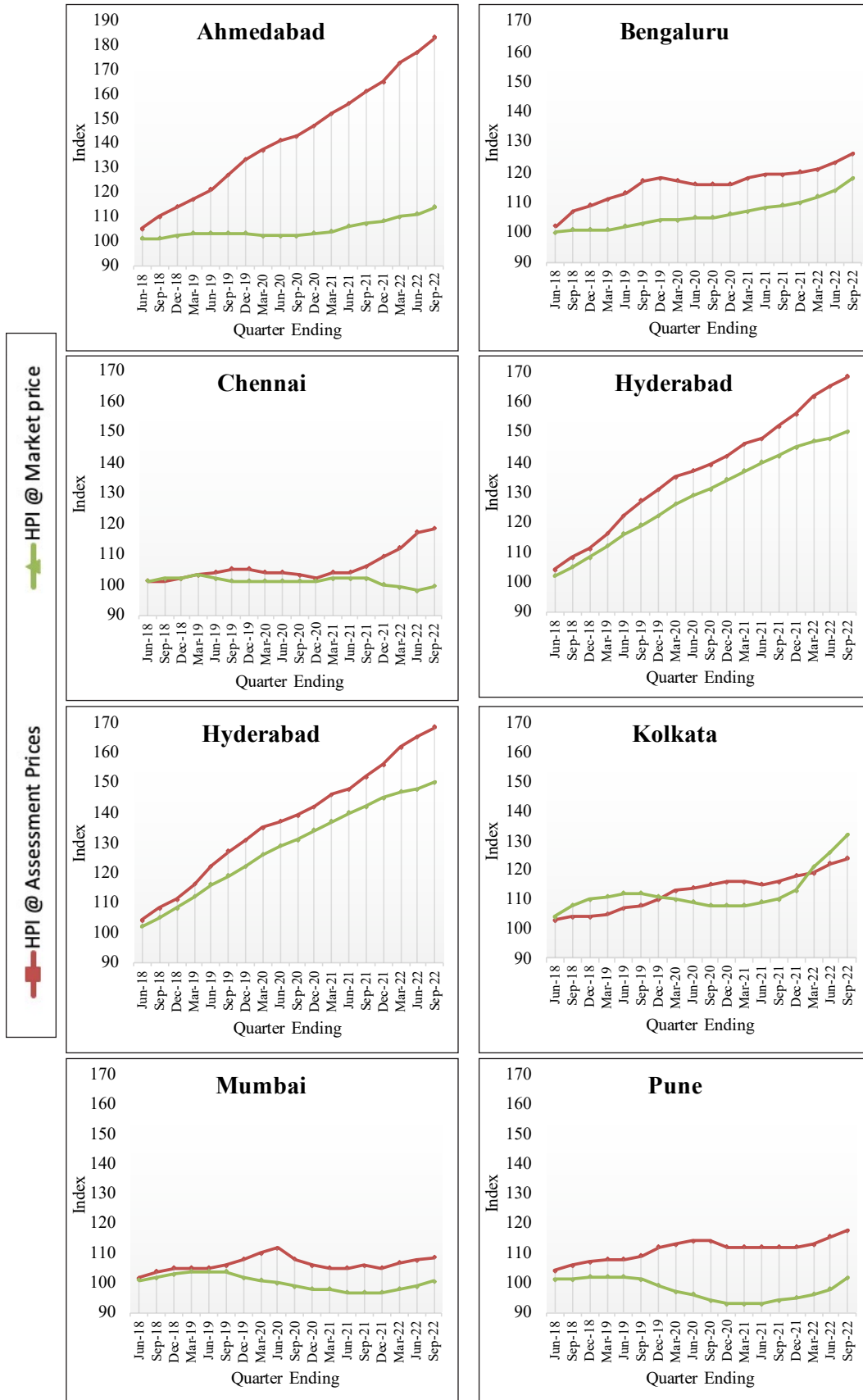
5.29 आवास की कीमतें आस्ति बाजारों में उतार-चढ़ाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं, जो आर्थिक असंतुलन उत्पन्न करती हैं। मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवास की कीमतों की निगरानी आवश्यक है। इन कीमतों में उतार-चढ़ाव घरेलू निधि और उपभोक्ता विश्वास पर इसके प्रभाव के माध्यम से उपभोग व्यय को प्रभावित करते हैं।

5.30 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) वित्त वर्ष 18 को आधार वर्ष मानकर दो आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), क्रमशः 'एचपीआई मूल्यांकन मूल्य' और 'एचपीआई बाजार मूल्य' त्रैमासिक प्रकाशित करता है। एचपीआई मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित है जबकि इसके विपरीत, एचपीआई बाजार मूल्य विकासक से न बेची गई सूची संग्रह के बाजार मूल्य पर आधारित है। भार के रूप में शहरों की जनसंख्या का उपयोग करके पूरे भारत के 50 शहरों के लिए समग्र सूचकांक की गणना की जाती है।

5.31 एचपीआई बाजार मूल्य में वार्षिक भिन्नता भुवनेश्वर में 37.7 प्रतिशत की वृद्धि से लेकर सितंबर, 21 को समाप्त तिमाही की तुलना में सितंबर 22 को समाप्त तिमाही (क्यूई) में इंदौर में 6.5 प्रतिशत के संकुचन तक थी। 50 शहरों में से 43 ने सूचकांक में वृद्धि दर्ज की, जबकि 7 शहरों में वार्षिक गिरावट देखी गई। देश के सभी आठ प्रमुख महानगरों, अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में वार्षिक आधार पर सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई।

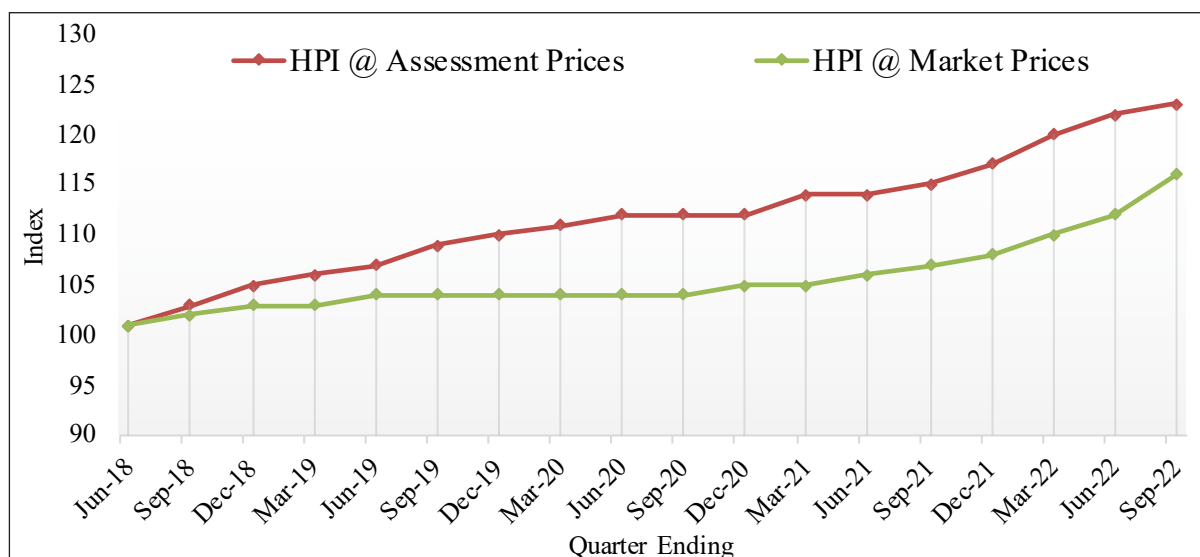
5.32 एचपीआई मूल्यांकन मूल्य में वार्षिक परिवर्तन अलग-अलग शहरों में व्यापक रूप से भिन्न है। जिसमें गांधीनगर में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि से लेकर सितंबर, 22 को समाप्त तिमाही में सितंबर, 21 को समाप्त तिमाही की तुलना में भिवाड़ी में 2.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। 50 शहरों में से, 46 शहरों ने सूचकांक में वृद्धि दर्ज की, जबकि 4 शहरों में वार्षिक आधार पर गिरावट देखी गई। देश के सभी आठ प्रमुख महानगरों के सूचकांक में वार्षिक वृद्धि देखी गई।

चित्र V.24: मेट्रो शहरों के लिए एचपीआई – ‘अहमदाबाद’ और ‘हैदराबाद’ में उछाल



स्रोत: रेजीडेक्स, एनएचबी

चित्र V.25: अखिल भारतीय समग्र एचपीआई - आवास बाजार में सुधार



स्रोत: रेजीडेक्स, एनएचबी

5.33 कोविड-19 संकट ने आवासीय रियल एस्टेट बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अप्रैल-जून, 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और घर पर रहने के आदेशों के कारण घरों की तलाश करने वाले खरीदारों की संख्या कम हो गई थी। इसके बाद, भारत के रियल एस्टेट उद्योग ने सितंबर, 2020 से गति पकड़ी और मार्च, 2021 में समाप्त होने वाली तिमाही में चरम स्तर तक पहुंच गया। महामारी की दूसरी लहर ने रियल एस्टेट क्षेत्र को फिर से प्रभावित किया जब बढ़ती अनिश्चितता और प्रतिबंधित आवाजाही के कारण घर खरीदारों ने खरीदारी में देरी की। तथापि, होम लोन की कम ब्याज दरों के साथ सरकार द्वारा समय पर किए गए नीतिगत हस्तक्षेप से वित्त वर्ष 23 के वहनीय खंड की मांग और आकर्षित खरीदारों की संख्या में अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई। समग्र एचपीआई मूल्यांकन और एचपीआई बाजार कीमतों में समग्र वृद्धि, आवास वित्त क्षेत्र में पुनरुद्धार का संकेत देती है। एचपीआई में स्थिर से मध्यम वृद्धि भी संपत्ति के बरकरार मूल्य के संदर्भ में घर के मालिकों और गृह ऋण फाइनेंसरों को विश्वास प्रदान करती है।

बॉक्स V.4: आवासन वित्त क्षेत्र (एचएफसी) को एनएचबी समर्थन

आवासन क्षेत्र के लिए गत 3 वर्ष चुनौती पूर्ण थे। पिछले तीन वर्षों में आवासन वित्तीय क्षेत्र को हो रही नकदी संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एनएचबी ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचान किए गए, व्यक्तिगत आवास ऋण पोर्टफोलियो सृजित करने के लिए, जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत आता है, एचएफसी को समर्थन देने के लिए वर्ष 2019 में नकदी समायोजन सुविधा योजना शुरू की गई थी।
- कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई द्वारा विशेष नकदी सुविधा के तहत प्रदान की गई ₹10000 करोड़ की राशि को वितरित करने के लिए विशेष पुनर्वित्तीय सुविधा (एसआरएफ) शुरू की गई थी और आरबीआई द्वारा अतिरिक्त विशेष नकदी सुविधा के तहत ₹5000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी।
- वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई द्वारा एसएलएफ-2 के तहत प्रदान की गई ₹10000 करोड़ की पूंजी के साथ एसआरएफ 2021 शुरू किया गया था। अपनी शुरुआत से एनएचबी ने ₹3.3 लाख करोड़ का पुनर्वित्तीय वितरण किया है, जिसमें से ₹0.84 लाख करोड़ वित्त वर्ष 03 वित्तीय वर्षों के दौरान वितरित किए थे।

- इसके अतिरिक्त आजादी का अमृत महोत्सव (एकएएम) के भाग के रूप में एनएचबी ने महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, अजा/अजजा, महत्वकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, तीसरे लिंग/दिव्यांगजन, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र एवं ग्रीन हाउसिंग सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए पुनर्वित्त के तहत 25/30 आधार बिंदु की छूट प्रदान की गई है।
- सीओपी26 में वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने की देश की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एनएचबी ने ग्रीन हाउसिंग के तहत ऋणों हेतु 100 बीपीएस की छूट दी है।
- एकएएम के भाग के रूप में और भौगोलिक रूप से सुदूर स्थित क्षेत्रों, जो कि देश की प्राथमिकता हैं, में ऋण को बढ़ावा देने के लिए एनएचबी ने पहचाने गए महत्वकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, तीसरे लिंग/दिव्यांगजन, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सितम्बर, 2023 तक ऋणों हेतु 100 बीपीएस छूट पुनर्वित्त देने का निर्णय लिया है।

भेषज मूल्य निर्धारण को नियंत्रित रखना

5.34 दवाओं की कीमतों के विनियमन के सिद्धांत नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग पॉलिसी, 2012 पर आधारित हैं, जिसे भेषज विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। नीति के प्रमुख सिद्धांत दवाओं की अनिवार्यता, सूत्रीकरण कीमतों पर नियंत्रण और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण हैं। 31 दिसंबर, 2022 तक, विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में 358 दवाओं के 890 सूत्रीकरणों के लिए राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2015 द्वारा अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएलईएम, 2022 लागू किया और एनएलईएम, 2022 को शामिल करते हुए भेषज विभाग द्वारा दिनांक 11.11.2022 को संशोधित औषधी की अनुसूची 1 (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) अधिसूचित किया गया था। दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक एनएलईएम, 2022 के तहत 119 सूत्रीकरणों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 2,196 सूत्रीकरण के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

5.35 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सभी को और विशेषतः गरीबों और वंचितों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनऔषधि केंद्र के रूप में जाने जाने वाले प्रतिबद्ध दुकान खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थायी और नियमित कमाई के अवसरों सहित स्वरोजगार भी प्रदान करते हैं। पीएमबीजेपी के अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक देश भर में 9000 से अधिक पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। वर्तमान में, पीएमबीजेपी की उत्पाद बास्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध 1759 दवाएं और 280 शल्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

निष्कर्ष

5.36 यह कोई इच्छाकल्पित चिन्तन नहीं है कि वर्ष 2023 अपने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम व्यापक आर्थिक अस्थिरता दिखाएगा। सीपीआई-सी और डबल्यूपीआई दोनों 6 प्रतिशत से नीचे गिर गए हैं (जो कि पूर्व के लिए आरबीआई की सहनशीलता की सीमा है) और वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले उछाल के अवरोही ढलान पर हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, इस वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के प्रमुख संवाहक, सामान्य स्तर पर लौट आए हैं और परिणामतः अन्य प्रमुख वस्तुओं की कीमतें भी सामान्य स्तर पर वापस आ गयी हैं। आरबीआई ने सामान्य मानसून की धारणा पर-वित्त वर्ष 24 की प्रथम तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत और-वित्त वर्ष 24 की द्वितीय तिमाही के लिए 5.4 प्रतिशत अनुमान लगाया है।

5.37 भारत का मुद्रास्फीति प्रबंधन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है और इसकी तुलना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से की जा सकती है जो अभी भी स्थिर मुद्रास्फीति दरों से जूझ रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्याशित मंदी के कारण, वैश्विक वस्तु कीमतों से आने वाले मुद्रास्फीति जोखिम वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कम होने की संभावना है। तथापि, मुद्रास्फीति पर बेहतर आधारभूत दृष्टिकोण के लिए समग्र जोखिमों के संदर्भ में, भारत की ऊपर की ओर जाने वाली दरें अनुमानित नीचे की ओर जाने वाले जोखिमों पर भारी हो सकता है। उदाहरणार्थ चीन में कोविड-19 के फिर से उभरने से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। दूसरी ओर, अगर चीन में कोविड-19 की स्थिति सामान्य होती है, तो वस्तु की माँग में उछाल आ सकता है - इस प्रकार वस्तु की कीमतों में हालिया गिरावट के स्थान पर उछाल देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना हाल के महीनों में बढ़ी है, और इससे तेल की अमेरिकी माँग में वृद्धि हो सकती है। इसी तरह, तेल से जुड़ी भू-राजनीति हमारी आयातित मुद्रास्फीति को विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है।

5.38 आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट भविष्य में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में भी वृद्धि की उम्मीद है। सामान्य तौर पर, दुनिया भर में जलवायु तेजी से अनिश्चित हो गई है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि का जोखिम और बढ़ गया है। बहुत कुछ औद्योगिक इनपुट कीमतों पर निर्भर करता है: वे कम हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर उपभोक्ता कीमतों में उनके विलंबित निकासी मूल मुद्रास्फीति की स्थिरता में अंशदान कर सकते हैं।

5.39 फिर भी, कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति की चुनौती इस वर्ष की तुलना में काफी आसान होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मौद्रिक और वित्तीय प्राधिकरण इस वर्ष की तरह ही सक्रिय और सतर्क रहेंगे।
